

# राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

**विषय:-** राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 28/08/2023 को संपन्न 473वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 473वीं बैठक दिनांक 28/08/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्कारे अध्यक्ष राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया-

1. डॉ. वी.लेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  2. श्री एन.के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  3. श्री किशान सिंह धुर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  4. डॉ. मनोज कुमार चौपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  5. श्री कलदिपुस तिळी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया-

**एजेन्डा आयटम क्रमांक-1:** 472वीं बैठक दिनांक 27/08/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 472वीं बैठक दिनांक 27/08/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष नीचे प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक-2:** गैर/मुख्य खनिजी एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति / टी.ओ.आर./अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स खम्हारडीह लाईन स्टीन माईन (प्रौ.- श्री पवन कुमार अध्यक्ष), राम-खम्हारडीह, लहरील-पधरिया, जिला-भुवेली (सचिवालय का मसौदा क्रमांक 2414)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नंबर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 428624 / 2023, दिनांक 11/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व ही संश्लिष्ट सूना पत्थर (गैर खनिज) खदान है। खदान राम-खम्हारडीह, लहरील-पधरिया, जिला-भुवेली जिला खसरा क्रमांक

195/1, 195/2, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/6 एवं 196/7, कुल क्षेत्रफल-0.66 हेक्टेयर में है। खदान की आवधिक उत्खनन क्षमता-4,977.17 टन प्रतिवर्ष है।

खदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैंक का विवरण -**

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विष्णु अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में कुना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 195/1, 195/2, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/6 एवं 196/7, कुल क्षेत्रफल-0.66 हेक्टेयर, क्षमता-4,977.17 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय समापन निर्धारण प्रधिकरण, जिला-मुनेली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 01/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 31/01/2022 के लिए वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 31/01/2023 तक वैध थी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार नुसारोपन नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (अग्नि शाखा), जिला-मुनेली के ज्ञापन क्रमांक 22/खलि.-02 उ.प./2023 मुनेली, दिनांक 18/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्षवार	उत्खनन (टन)
2018-19	2,800
2019-20	4,700
2020-21	4,375

2021-22	4,775
2022-23 (जनवरी 2023 तक)	3,950

- समिति का मत है कि दिनांक 01/02/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संकेत में ग्राम पंचायत रामबोड़ का दिनांक 20/04/2002 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
  3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एंथ्रॉप क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संघटक (खनि प्रशासन) जिला-बलीदाबाजार-भटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1500/खलि/तीन-1/2016 बलीदाबाजार, दिनांक 08/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।
  4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1000/खलि-02/2020 मुंगेली, दिनांक 28/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरेखित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 7.52 हेक्टेयर है।
  5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 998/खलि-02/2020 मुंगेली, दिनांक 28/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, कुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एंथ्रॉप, बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
  6. लीज का विवरण - लीज श्री पवन कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 15 वर्ष अर्थात् दिनांक 19/08/2017 से 18/08/2032 तक की अवधि हेतु है।
  7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 195/3 भी हीरा लाल एवं खसरा क्रमांक 195/1, 195/2, 195/3, 195/6, 195/7, 195/8, 196/1, 196/2, 196/4, 196/6 एवं 196/7 आरेखक के नाम पर है। समिति का मत है कि उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
  9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.दि./3421 बिलासपुर, दिनांक 17/05/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
  10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-भकुरीडीह 810 मीटर, स्कूल ग्राम-भकुरीडीह 1 कि.मी. एवं अस्पताल बिला 9.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 235 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2130 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 840 मीटर, तालाब 560 मीटर, नाला 300 मीटर एवं नहर 137 मीटर दूर है।

11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संन्धीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विंटिली पील्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र निम्न नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - अनुमोदित ब्यारी प्लान अनुसार त्रिखोलीजिकल रिजर्व 1,15,500 टन, काईनेबल रिजर्व 52,908 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 47,814 टन है। वर्तमान में त्रिखोलीजिकल रिजर्व 92,611 टन, काईनेबल रिजर्व 30,016 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 27,014 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,651.52 वर्गमीटर है। औपन काल्ट सेमी मेकेंनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लानिटिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में अक्षर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़कल किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	4,761.03	षष्ठम	4,760.74
द्वितीय	4,761.01	सप्तम	4,977.17
तृतीय	4,761.13	अष्टम	4,510.28
चतुर्थ	4,761.12	नवम	4,808.68
पंचम	4,791.71	दशम	4,925.09

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेंट्रल प्रायमरिड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी उत्खनित होने के कारण लीज क्षेत्र से लगी हुई भूमि खतरा ब्लॉक 196/5 एवं 197/2 में 174 मीटर लम्बाई तक 4 पकितियों में 348 नग एवं 50 मीटर लम्बाई तक 3 पकितियों में 78 नग, इस प्रकार कुल 423 नग वृक्षारोपण किया जाना है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया गया कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी के कुल क्षेत्रफल अनुसार 3 पकितियों में 528 नग वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। अतः शेष 100 नग पौधों का वृक्षारोपण सी.ई.आर. के तहत किये जाने वाले (पवित्र वन निर्माण या नदी के किनारे) वृक्षारोपण में अतिरिक्त शामिल करके हुए पूर्ण किया जाएगा। समिति का मत है कि उपरोक्त वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समकालर व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,651.52 वर्गमीटर क्षेत्र है, जो

8 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खारी प्लान में किया गया है। प्रतिवर्षित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उत्तर है। अतः जीव उपसंहार निम्नानुसार विधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उत्खननीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीम कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 5(a) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जलस्तर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2023 से प्रारंभ किया गया है। उक्त को संघ में दिनांक 27/02/2023 को सूचना दी गई थी।

18. नानवीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल सेक्टर, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र चण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपसंहार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—मुंगेरी के द्वापन क्रमांक 1000/खलि-02/2020 मुंगेरी, दिनांक 28/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें क्षेत्रफल 7.52 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (प्लान—खम्हारबीह) का रकबा 0.88 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्लान—खम्हारबीह) को मिलाकर कुल रकबा 8.18 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचार उपायों (Remedial Measures) के संघ में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के निरोध हेतु आवश्यक उपायों का वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों

बाधात संघालक, संघालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्न, इद्रावटी भवन, नवा रावपुर अटल नगर, किला - रावपुर (छलीसगड) को पत्र लेख किया जाए।

3. इतिबंधित 7.5 मीटर चौडी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन कये जाने पर जीव उपचलत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्न एवं पर्यावरण को सति पहुंचाने हेतु छलीसगड पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रावपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रावपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन इतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकटित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एन.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति दी गई-
  - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - ii. Project proponent shall submit the previous year production detail from 01/02/2023 to till date from the mining department.
  - iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
  - iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
  - v. Project proponent shall submit the Land owner consent letter for mining.
  - vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
  - vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
  - ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
  - x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
  - xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
  - xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and

Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

- iii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of plantation works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स फुईया सेम्ड नार्डन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत फुईया, ग्राम-फुईया, तहसील व जिला-कोरबा (सचिवालय का नक्सी क्रमांक 2415)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर- एसआईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 428881/2023, दिनांक 11/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (बीम खनिज) है। खदान ग्राम-फुईया, तहसील व जिला-कोरबा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 638, कुल क्षेत्रफल - 1.173 हेक्टर में प्रस्तावित है। उत्खनन फुईया नाला से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता - 9.518 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 23/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/08/2023

बस्तुनिष्ठता हेतु श्री शिवराज सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत बुईया उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली बस्तुतुल्य जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुईया का दिनांक 01/02/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र बस्तुतुल्य किया गया है।
3. विन्दाकित/सीमांकित — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना — माईनिंग प्लान बस्तुतुल्य किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरबा के ड्राफ्ट क्रमांक 937/खनिज/उ.पा.अ./2023-24 कोरबा, दिनांक 09/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के ड्राफ्ट क्रमांक 934/कले./खनिज/2023 कोरबा, दिनांक 08/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर की मीटर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के ड्राफ्ट क्रमांक 922/कले./खनिज/2023 कोरबा, दिनांक 08/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुस्सुदारा, मरघट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। खदान के ड्राउनस्ट्रीम में 131 मीटर की दूरी पर एनीकट स्थित है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत बुईया के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के ड्राफ्ट क्रमांक 732/खनि-2/2023 कोरबा, दिनांक 06/04/2023 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु है। जारी एल.ओ.आई. में "गौन खनिज साधारण रेत हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हेतु यह आरक्ष-पत्र (LOI) जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, कोरबा (वनसम्पदा), जिला-कोरबा के ड्राफ्ट क्रमांक/लक.अ./1883 कोरबा, दिनांक 14/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र बस्तुतुल्य किया गया है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति बस्तुतुल्य की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवासीय ग्राम-बुईया 700 मीटर, स्कूल ग्राम-बुईया 1 कि.मी. एवं अस्पताल बाल्को नगर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. राज्यमार्ग 21 कि.मी. दूर है। खदान के ड्राउनस्ट्रीम में 131 मीटर की दूरी पर एनीकट स्थित है। स्वीकृत रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुनः स्थित नहीं है।



11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 68 मीटर, न्यूनतम 26 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 683 मीटर, न्यूनतम 582 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 28 मीटर, न्यूनतम 13 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 21 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है।

12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेत की मात्रा-9,518 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.685 मीटर से अधिक है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन के दौरान पानी आने के कारण और अधिक गहराई तक रेत उत्खनन नहीं किया गया।

13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलिंग – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल 25 मीटर गुना 25 मीटर के विच किन्दुओं पर दिनांक 01/06/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवलिंग (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरंत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. गैर माईनिंग क्षेत्र – खदान के 131 मीटर काउन्टरटीम में एनीकट किया है। नवे माइजिंगनुसार अनुसार एनीकट की दूरी खदान के अपरटीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा काउन्टरटीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार एनीकट से न्यूनतम 250 मीटर दूरी छोड़ते हुये 2,212 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के असीम 9,518 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

15. कॉन्सीरेट पर्मावल्गीव दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से पर्चा उपरंत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
10.97	2%	0.219	Following activities at Nearby Village- Chuiya	
			Plantation in Village Boundary	0.354
			TOTAL	0.354

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम चुईया के बाजार हाट तालाब के किनारे चारों ओर कुल 50 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम, जाम, इमली आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद के लिए राशि 500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 3,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 26,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,400 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस बाबत ग्राम पंचायत चुईया का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त कार्य को किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
17. वृक्षारोपण कार्य - ग्राम पंचायत द्वारा वृक्षारोपण हेतु सहमति प्राप्त भूमि खसरा क्रमांक 705 के 108.3 हेक्टेयर में से 1.0 हेक्टेयर क्षेत्र पर (पीपल, नीम, आम, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 28,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 88,000 रुपये, खाद के लिए राशि 4,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 18,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,38,000 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 84,800 रुपये आगामी 4 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त कार्य को किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
18. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर रीर माईनिंग क्षेत्र में सीमा स्थापित करना आवश्यक है। साथ ही लीज क्षेत्र के चारों ओर तथा सीमा लाईन के कन्ट्रोल में सीमेंट के खम्भे लगाया जाना आवश्यक है, ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
19. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रस्तावक पदाधिकारी/पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
20. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भरवाई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भरवाई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावे। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वर्तिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। चुईया नाला छोटी नदी है तथा इनके उर्वरकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. अलोदित खदान (ग्राम-चुईया) का रकबा 1.173 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी नहीं।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Situation Study) करायेंगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत

सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघ, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. लीज क्षेत्र की साहज का बेसलाईन डाटा –

- i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर नदी में रेत की साहज के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तालकल एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
  - ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं छिद्र बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपरस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साहज के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर किया जायेगा।
  - iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं छिद्र बिन्दुओं पर रेत साहज के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
  - iv. रेत साहज के पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर रेत साहज के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 8 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसाध्वि के नेतृत्व सुईया रोपड माईन (सचिव/ससंच, ग्राम पंचायत सुईया), पोस्ट ऑफ ससरा जमाक 838, ग्राम-सुईया, तहसील व जिला-कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 1.173 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 2.212 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 0.9518 हेक्टेयर उत्खनन हेतु क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 8.710 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्काशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई भविकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेली द्वारा किया जाएगा।
5. सस्टेनेबल रोपड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर रोपड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर रोपड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सुधिया किया जाए।

3. मैसर्स अमलडीहा रोपड कार्बन (प्री.- श्री नितेश चन्द भार्गव), घान-अमलडीहा, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2418)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर- एल.ओ.आई./ सीजी/ एम.ओ.आई./ 428983/2023, दिनांक 11/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। खदान घान-अमलडीहा, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर स्थित प्लॉट ऑफ खसरा क्रमांक 512, कुल क्षेत्रफल-4.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता-77,710 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

सद्वानुसार परियोजना प्रस्तावक को एल.ओ.आई. चलीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिवेक यादव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. घान पंचायत का अनापति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में घान पंचायत अमलडीहा का दिनांक 12/01/2018 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. किन्हाकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान किन्हाकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संकलक (ख. प्रशा.) जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 252/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2023 बिलासपुर, दिनांक 27/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 253/खनि/रेत/प्रमाण पत्र/2023 बिलासपुर, दिनांक 27/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 253/खनि/रेत/प्रमाण पत्र/2023 बिलासपुर, दिनांक 27/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्री नितेश चन्द भार्गव के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3335/खनि/रेत नीलागी/2023 बिलासपुर, दिनांक 17/03/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 साल हेतु वैध है। जारी एल.ओ.आई. में रेत खदान

- उत्खनन पट्टा अवधि 2 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण हेतु यह अवकाश पत्र जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
  10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आकादी जाम-अमलडीहा 340 मीटर, स्कूल जाम-अमलडीहा 400 मीटर एवं अस्पताल कसबोल 9.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29.35 कि.मी. राजमार्ग 9.35 कि.मी. दूर है। तालाब 170 मीटर, सड़क 200 मीटर, नहर 1.2 कि.मी., नाला 1.9 कि.मी. एवं एनोकेट 7.6 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनोकेट स्थित नहीं है।
  11. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 530 मीटर, न्यूनतम 510 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 263 मीटर, न्यूनतम 258 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 160 मीटर, न्यूनतम 155 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 62 मीटर, न्यूनतम 60 मीटर है।
  12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधानित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 77,710 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4.09 मीटर है। खनन की दौरान औसत 3.55 मीटर गहराई में पानी आने के कारण अधिकतम औसत गहराई 4.09 मीटर तक ही किया जा सके। रेत की वास्तविक गहराई हेतु योजनामा प्रस्तुत किया गया है।
  13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों ओर 25 मीटर गुण 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 29/03/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरंत खोटाघापना सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
  14. कॉन्सीरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरंत निम्ननुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

31.42	2%	0.6284	Following activities at Nearby, Village- Amaldiha	
			Plantation around the village pond	0.50
			<b>Total</b>	<b>0.50</b>

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के घाटी और कुल 30 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन, कटहल आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,000 रुपये, ट्टी-गार्ड के लिए राशि 4,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 66,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ज्ञान पंचायत अमालडीहा की सहमति उपरोक्त पञ्चयोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 298, क्षेत्रफल 1.39 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
16. वृक्षारोपण कार्य – नदी तट में 800 नग एवं पट्टुच मार्ग में 200 नग, इस प्रकार कुल 1000 नग (अर्जुन, जामुन, हीराम, करंज, कदंब आदि) पौधों के वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 80,000 रुपये, पौंसिंग के लिए राशि 1,20,000 रुपये, खाद के लिए राशि 40,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,50,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,90,000 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 7,80,000 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि नदी के घाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाए।
17. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्लुजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. खदान के आस-पास नदी तट एवं पट्टुच मार्ग में सड़न वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. छत्तीसगढ़ अदरश पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियम का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लंबित नहीं है।

23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य को मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
26. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं मत्तई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः मत्तई का कार्य मैन्युअल विधि से ही कराई जावे। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की पारिस्थितिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। शिवनाथ नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम-अमलझीहा) का रकबा 4.09 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में अगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अध्ययन (Situation Study) करायेंगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाका सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसमिति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाइन डाटा -
  1. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के सारी (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
  2. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही छिद्र बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दीनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सारी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर किया जायेगा।

- iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं फिज बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस Levels का मापन किया जाएगा।
  - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित फिज बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।
  4. अधोदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सहाय अनुमति की जाती है।
  5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरत सर्वसम्मति से मेसर्स अमलडीहा रोम्ब माईनिंग (प्री- वी निलेश चन्द भार्गव), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 512, ग्राम-अमलडीहा, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.09 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-02 में बर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई मजदूरों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी जालों/बन्नी का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जाएगा।
  6. सस्टेनेबल रोम्ब माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर रोम्ब माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
  7. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर रोम्ब माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स बस्तर बोटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (आयरेक्टर-श्री सुपंक चन्दाकर), ग्राम-बुसगांव, तहसील-सोहाण्डीगुड़ा, जिला-बस्तर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 2417)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनबी2/428828/2023, दिनांक 12/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-बुसगांव, तहसील-सोहाण्डीगुड़ा, जिला-बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 592/1, कुल क्षेत्रफल-1.21 हेक्टेयर में बहुआयु फलीवर बेस्ड स्प्रिट डिस्टलरी क्षमता - 1.0 की.एल.





की एवं खुदजा फ्लॉवर बेसड आई.एम.आई.एल. (पोर्टेबल कन्टी लिक्वर) कौंटिंग लाइन समता - 250 किलो प्रतिदिन हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रूप 3.65 करोड़ होगा।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ड्राफ्ट दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई व्यक्ति जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

**5. मेसर्स कुदुरमाल सेण्ड माईन (सचिव/सचिव, ग्राम पंचायत कुदुरमाल), ग्राम-कुदुरमाल, तहसील व जिला-कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2418)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर- एसआईए/ सीपी/ एमआईएन/ 429125/2023, दिनांक 12/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। खदान ग्राम-कुदुरमाल, तहसील व जिला-कोरबा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हसदेव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता-57,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ड्राफ्ट दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय कुमार चंडा, सचिव, ग्राम पंचायत कुदुरमाल उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अडलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संकल में ग्राम पंचायत कुदुरमाल का दिनांक 13/03/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज हाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरवा के ड्राफ्ट क्रमांक 938/खनिज/उ.पा.अ./2023-24 कोरवा, दिनांक 09/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरवा के ड्राफ्ट क्रमांक 949/खनिज-/2023 कोरवा, दिनांक 11/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की वीर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरवा के ड्राफ्ट क्रमांक 947/खनिज-/2023 कोरवा, दिनांक 11/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, नरघट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. सचिव/सामग्री धाम पंचायत कुदुरमाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरवा के ड्राफ्ट क्रमांक 789/खनिज-2/2023 कोरवा, दिनांक 17/04/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है। जारी एल.ओ.आई. में "गौण खनिज साधारण रेत हेतु उत्खनन पट्टा किलेख को पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हेतु यह आशय-पत्र (LOR) जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, कोरवा वनसम्पदा, जिला-कोरवा के ड्राफ्ट क्रमांक/उ.पा.अ./1865 कोरवा, दिनांक 14/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 3.45 कि.मी. की दूरी पर है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घाम-कुदुरमाल 360 मीटर, स्कूल घाम-कुदुरमाल 600 मीटर एवं अस्पताल उरगा 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 500 मीटर एवं राज्यमार्ग 2.4 कि.मी. दूर है। तालाब 850 मीटर, नाला 390 मीटर, नहर 740 मीटर एवं टोड ब्रिज 1.3 कि.मी. दूर है। खदान के 385 मीटर ऊपरनस्ट्रीम में एनीकट स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल स्थित नहीं है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 680 मीटर, न्यूनतम 585 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 400 मीटर, न्यूनतम 398 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 101 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 180 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा-87,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सट्ट

*(Handwritten Signature)*

की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड़ई (Pits) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4 मीटर है। खनन के दौरान औसत 3.13 मीटर गहराई में पानी आने के कारण अधिकतम औसत गहराई 4 मीटर तक ही किया जा सका। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों ओर 25 मीटर गुणा 25 मीटर के डिश बिन्दुओं पर दिनांक 29/04/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/प्रस्ताविका प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय सर्विला (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35.50	2%	0.71	Following activities at Nearby, Village- kudumal	
			Plantation around the village pond	0.50
			<b>Total</b>	<b>0.50</b>

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत सालब के चारों ओर कुल 30 नए पीछे को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम और जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछे के लिए राशि 3,000 रुपये, ट्री-गार्ड के लिए राशि 4,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 88,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा राम पंचायत कुदुमाल के सहभूति उपखंड पद्यारोपण स्थान (लालाब के चारों तरफ क्रमांक 271, क्षेत्रफल 1.931 हेक्टेयर) की संख्या में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. वृक्षारोपण कार्य – नदी तट में 800 नम एवं पट्टुव नर्म में 200 नम, इस प्रकार कुल 1000 नम (अर्जुन, जामुन, सीरस, करंज, कदंब आदि) पीछे के वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछे के लिए राशि 80,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,20,000 रुपये, खाद के लिए राशि 40,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,50,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,90,000 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 7,80,000 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि नदी के घाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाए।

17. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पब्लिसिटी डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़कण की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. खदान के आस-पास नदी तट एवं पटुंग मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. छत्तीसगढ़ आवर्त पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लंबित नहीं है।
23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 की common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 की writ petition (S) Civil No.114 (2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) दिया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माइनेबल रिजर्व का 80 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा एवं खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेड माइनिंग गाइडलाइन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाइडलाइन फॉर सेड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
26. पर्यावरण स्वीकृति में दिए गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं अर्थाविक पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा करादे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
28. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं भरई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है।

आत बराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावे। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं लंबांकवी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। इससे नदी कड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

1. आवेदित खदान (घाम-कुदुरमाल) का लम्बा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राउंड अध्ययन (Situation Study) करायेंगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधित नहीं हो सके। रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनस्वस्थि, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

#### 3. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -

- a. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तात्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
- b. फीस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं विभिन्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।
- c. इसी प्रकार रेत खनन उपरान्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
- d. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। फीस्ट-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं वी-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से मैसर्स कुदुरमाल सीम्स माईनिंग (सत्यम/सचिव, घाम बंदाघाट कुदुरमाल), प्लॉट ऑफ़ खसरा क्रमांक 01, घाम-कुदुरमाल, तहसील व जिला-कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 38,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-03 में उल्लिखित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी

वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहना। सीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लॉन्ड्रिंग प्लांट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं एन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. एन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में पलखानन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सुधिया किया जाए।

6. वेल्स विन्हेस्टर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2), घाम-घरीदा, तहसील-धरसीवा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2419)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 429133/2023, दिनांक 13/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा घाम-घरीदा, तहसील-धरसीवा, जिला-रायपुर स्थित प्लॉट नं 19 स्थित खसरा क्रमांक 717/3 एवं 717/4, कुल क्षेत्रफल-0.717 हेक्टेयर में रि-रोल्ल प्रोडक्ट्स (यू रि-ड्रिटिंग कर्नेस फिब्र कोल बेस्ड गैसीफायर) क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल निवेश 8 करोड़ रुपये होगा।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निखिल आहुजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. घाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उद्योग की स्थापना के संबंध में घाम पंचायत घरीदा का दिनांक 03/09/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. जल एवं वायु सम्मति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि-रोल्ल प्रोडक्ट्स क्षमता (यू रि-ड्रिटिंग कर्नेस फिब्र कोल बेस्ड गैसीफायर) - 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 18/11/2020 को जारी की गई, जो कि उत्पादन प्रारंभ तह के प्रथम दिन से 12 माह की अवधि तक वैध थी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई

कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु उत्तरीसमूह पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी उत्तरीसमूह पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. मू-स्वामित्व – मू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार भूमि विधेयवार इस्रात प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है।

4. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ आबादी ग्राम बरोदा 1 कि.मी., स्कूल बरोदा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल उरला 11.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन मांडर 8 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तान, माना, रायपुर 23.5 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 600 मीटर एवं राज्यमार्ग 8.5 कि.मी. दूर है। खासल नदी 4.9 कि.मी. एवं कुल्हन नाला 5.5 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, परिसिधित्वीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविकिरण क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिकेवित किया है।

5. सैम्पल एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Particular	Area in (Sq.M)	Area in (%)
1.	Rolling Mill Area	1,363	19.01
2.	Raw Material Area	375	5.23
3.	Finished Products Area	375	5.23
4.	Parking	208	2.9
5.	Office	135	1.88
6.	Green Belt	2,868	40
7.	Road Area	1,143	15.94
8.	Open Area	703	9.81
	<b>Total</b>	<b>7,170</b>	<b>100</b>

6. री-मटेरियल :-

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Ingots/Billets	31,500	Local Market & Outside of State	By road

7. प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of existing Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 TPA

8. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – वर्तमान में रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में ईंधन को रूप में कोयले को कोल गैसीफायर के माध्यम से गैस का उपयोग किया जाता है। कोल गैसीफायर से जनित टॉर को अधिकृत कोल टॉर इकाई को प्रदाय किया जाना बताया गया है। कोल गैसीफायर आधारित रि-हीटिंग फर्नेस रोलिंग मिल में उच्च दखला का वेट स्कबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चिमनी से पार्टिकुलेट

सेक्टर का उत्सर्जन 50 मिलियन/सामान्य घनमीटर रखा जाता है। पर्युजिटीय डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

9. **ग्रीस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था** - सेलिंग मिल से मिल स्कील-800 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग-700 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट को रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्कील एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** -

- **जल खपत एवं स्रोत** - परियोजना हेतु प्रारंभ में कुल 12 घनमीटर (वन टाईम) जल की आवश्यकता होती है। परियोजना के निर्धारित संयोजन हेतु प्रेश वॉटर कुल 9 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, परेसु उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं वीन बेल्ड एवं डस्ट स्टोरान हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति मू-जल से की जाती है। समिति का मत है कि मू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल वाटरमैड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपयुक्त जलित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। परेसु दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शुन्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **मू-जल उपयोग प्रबंधन** - उद्योग स्थल सेंट्रल वाटरमैड वाटर बोर्ड के अनुसार सभी किटिकल जोन में जाता है। जिसके अनुसार-

(अ) दुहद एवं कचम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) वाटरमैड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक घग्घा रेनवाटर हार्वेस्टिंग/ऑप्टिमाइज्ड जल रिचार्ज के आधार पर मू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल वाटरमैड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** - रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति कमी** - वर्तमान में परियोजना हेतु 1000 किलो.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 किलो.ए. क्षमता का 1 नग किलो. सेट स्थापित किया जाएगा।

12. **दूषारोपण संबंधी जानकारी** - हलिल परिट्यन के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.284 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 710 दूषारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि दूषारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुकसा हेतु कॅसिंग, खाद एवं सिंचाई लगा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षावन घटकवार एवं समसवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।





13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 के मध्य किया गया। उक्त के संबंध में सूचना दी गई।
14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैंडर्ड टर्म ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एन.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायर्समेंट स्कीपरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन-फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.
- ii. Project proponent shall submit the plant layout plan alongwith KML file.
- iii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
- iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- v. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.
- vi. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.
- vii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.
- viii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.
- ix. Project Proponent shall submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.
- x. Project proponent shall submit the details of solid waste generation from the unit.

- xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xiii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.
- xv. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 604(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xviii. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of 40%.
- xix. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xx. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.
- xxi. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिकरण (एल.ई.आई.ए.ए.) घलीसयड को तदानुसार सुधित किया जाद।

**7. केसरी सीधुरी स्टील एम्ड पावर एल.एल.सी., ग्राम-उरला, तहसील व जिला-राधपुर (सुधिवालय का नसती क्रमांक 2420)**

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएलसी/ 428204/2023, दिनांक 13/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-उरला, तहसील व जिला-राधपुर स्थित खसरा क्रमांक 282/1, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 282/8, 284/4, 284/5, 284/6, 284/7 एवं 297/2 स्थित

कुल क्षेत्रफल-2443 हेक्टेयर में रि-रोलिंग स्टील प्रोडक्ट्स (सी.टी.डी. बार्स एण्ड राउण्ड्स, फ्लैट रोवर्स, टी.एम.टी. बार्स) क्षमता - 17,700 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 2 करोड़ रुपये होगा।

उक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक को एआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. जल एवं वायु सम्बन्धी -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा सी.टी.डी. बार्स एण्ड राउण्ड, फ्लैट रोवर्स, टी.एम.टी. बार्स, क्षमता-17,700 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 31/08/2023 को जारी की गई, जो दिनांक 31/03/2025 तक वैध है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. एल.एल.पी (Limited Liability Partnership) एडीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार श्री मनोज कुमार अग्रवाल, श्रीमती रेनु अग्रवाल एवं श्री धवल अग्रवाल, लिमिटेड लाईमििटी पार्टनर है।

3. भू-स्वामित्व - भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार भूमि श्रीमती रेनु अग्रवाल के नाम पर है।

4. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -

- समीपस्थ आबादी घाट-बेड़ी 400 मीटर एवं रायपुर नगर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन रायपुर 7.9 कि.मी. एवं राष्ट्रीय विदेकानंद विमानपत्तान, माना, रायपुर 21 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.6 मीटर दूर है। खासून नदी 2.1 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट -

S.No.	Particular	Area in (Sq.M)	Area in (%)
1.	Rolling Mill Area	5,252.45	21.5
2.	Raw Material	1,954.40	8
3.	Finished Goods Area	2,320.85	9.5

4	Cooling Shed	877.20	4
5	Office	610.75	2.5
6	Greenbelt	8,065.00	33.01
7	Road Area	3,849.25	15.75
8	Open Area	1,400.10	5.74
	<b>Total</b>	<b>24,429.9</b>	<b>100</b>

6. ई-मटेरियल :-

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets	18,500	Open Market	By road

7. प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of existing Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products - 17,700 TPA

a. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - वर्तमान में रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में ईंधन के रूप में फर्नेस ऑयल का उपयोग किया जाता है। स्थापित रि-हीटिंग फर्नेस रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का वेट स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की धिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित धमनी से पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/साधारण घनमीटर रखा जाता है। पड़ोसीय कस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

b. लोक अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था - रोलिंग मिल से मिल स्केल-450 टन प्रतिवर्ष एवं एम्ब कटिंग-350 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एम्ब कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही युज्ड ऑयल 0.1 किलोलीटर प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसे अधिकृत इकाई को विक्रय हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल खसत एवं स्त्रोत - परियोजना हेतु प्रारंभ में कुल 14 घनमीटर (बन टाईम) जल की आवश्यकता होती है। परियोजना के नियमित संचालन हेतु क्रेस वीटर कुल 8 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1.5 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं कस्ट संचालन हेतु 2.5 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। समिति का मत है कि भू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल साराम्ब वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - औद्योगिक प्रक्रिया से कृत्रिम उपचार प्राप्त दूषित जल को उखा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं लोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति बची जाती है।

- भू-जल उपयोग प्रबंधन - उद्योग स्थल सेंट्रल साराम्ब वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल ज़ोन में आता है। जिसके अनुसार-

(अ) बृहद एवं माध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत शुद्धित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) घाउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्बेस्टिंग / ऑटिफिशियल जल रिचार्ज के अन्तर्गत न्यू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल घाउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्बेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

11. रेन वाटर हार्बेस्टिंग व्यवस्था – रेन वाटर हार्बेस्टिंग व्यवस्था की गणना सहित जानकारी फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाने प्रस्तावित है।
12. विद्युत आपूर्ति स्वीत – वर्तमान में परियोजना हेतु 2 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।
13. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.81 (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,450 नव वृक्ष रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है एवं वृक्षारोपण हेतु (वृक्षों की संख्या सहित) वृक्षों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, छाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समग्रवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वेरलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 के मध्य किया गया। उसी के संक्षेप में सूचना दी गई।
15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार " The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्बन्धी से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एन.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजिस्टरिंग इन्वायल्ट वरीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित क्लॉज 3(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फैरस एण्ड नॉन-फैरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chattagadh Environment Conservation Board of air and water consent.
- ii. Project proponent shall submit the plant layout plan alongwith KML file.
- iii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
- iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- v. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.
- vi. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.
- vii. Project Proponent shall submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.
- viii. Project proponent shall submit the revised land area statement with green belt of atleast 40% of the total area.
- ix. Project proponent shall submit the details of solid waste generation from the unit.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.
- xiv. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvii. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of 40%.
- xviii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation

incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

- xix. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.
- xx. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. बेसल घवईपुर रोम्ब कार्डिन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत घवईपुर, ग्राम-घवईपुर, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2421)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429131/2023, दिनांक 13/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (नीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-घवईपुर, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा स्थित खतरा क्रमांक 570, कुल क्षेत्रफल-4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन अधिरन नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता-27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती सारदा देवी कोलम, सरपंच एवं श्री खंदन सिंह कंवर, सचिव, ग्राम पंचायत घवईपुर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घवईपुर का दिनांक 23/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - कार्डिन प्लान विथ रोम्ब डिप्लेनिंगमेंट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 823/खनिज/उ.ख.अ./2023-24 कोरबा, दिनांक 25/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 824/खनि- /2023 कोरबा, दिनांक

25/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के आपन क्रमांक 824/खनि- /2023 कोरबा, दिनांक 29/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनिकेट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. सचिव/संरक्षक, राम पंचायत धवाईपुर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के आपन क्रमांक 770/खनि-2/2023, कोरबा दिनांक 17/04/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु है। जारी एल.ओ.आई. में "नीचे खनिज साठानन रेत हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीवन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय-पत्र (LOI) जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमंडल कटघोरा, जिला-कोरबा के आपन क्रमांक/तक.अधि/2023/1586 कटघोरा, दिनांक 16/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-धवाईपुर 320 मीटर, स्कूल राम-डेलवाडीह 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल राम-डेलवाडीह 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.4 कि.मी. दूर है। रोड विज 1.1 कि.मी. एवं तालाब 630 मीटर दूर स्थित है।
11. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिकतम 158 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 897 मीटर, न्यूनतम 895.8 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 50.24 मीटर, न्यूनतम 50.18 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 38 मीटर, न्यूनतम 19 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई- 1.5 मीटर, तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई-1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा-27,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.12 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 28 मीटर गुंथा 25 मीटर के पिठ किन्दुओं पर दिनांक 19/09/2023 को रेत सतह



के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें छविज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **कैपिटल पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष वित्तार से कार्य उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35.62	2%	0.7184	Following activities at Village- Dhawaipur	
			Plantation	0.7184
			<b>Total</b>	<b>0.7184</b>

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (पीपल, जामुन, नीम, बरगद, आंवला आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नम पीपल के लिए राशि 5,000 रुपये, ट्री-गार्ड एवं फेंसिंग के लिए राशि 24,340 रुपये, खाद के लिए राशि 7,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 38,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 71,840 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 30,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत धावापुर के सहमति उपरान्त पद्यायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 507, क्षेत्रफल 1 हेक्टर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट में 800 नम, स्कूल में 200 नम एवं पट्टुव मार्ग में 200 नम, इस प्रकार कुल 1,000 नम किया जाना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी तट, स्कूल एवं पट्टुव मार्ग में 1,000 नम वृक्षारोपण किये जाने हेतु संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उपरोक्त वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीपल, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं वार्षिकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही नदी तट, स्कूल एवं पट्टुव मार्ग की खसरा संबंधी जानकारी एवं सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

नदी के घाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाना आवश्यक है।

17. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोवराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

18. रीत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं भराई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीडर जैसे वरिष्ठ भारी काढ़न की श्रेणी के हैं।

अतः भरवाँ का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावे। नदी में भारी वाहन, मशीनें, घास आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रखा जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं लताबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अहिरन नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार कुल लीज क्षेत्रफल 45,000 वर्गमीटर में से 80 प्रतिशत क्षेत्रफल 27,000 वर्गमीटर में 1 मीटर की गहराई तक रेत का उत्खनन प्रस्तावित किया गया है, जिसके अनुसार 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रस्तावित किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्बन्धि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (घाम-घवईपुर) का रकबा 4.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाध नही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का रेसलाईन डाटा —
  - i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरी (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
  - ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।
  - iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (जुई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
  - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 8 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. नदी के घाट में कुआरोपण बाढ़ की सीमा (Flood level) की ध्यान में रखी हुई 800 नग, सहूल में 200 नग एवं पहुँच मार्ग में 200 नग, इस प्रकार कुल 1,000 नग कुआरोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में कुआरोपण (80 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीसी, पॉसिंग, खाद एवं सिंचाई

तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव एवं नदी तट, स्कूल तथा पहुंच मार्ग की खसरा संकीर्ण जानकारी सहित सहमति पत्र को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों अनुमति की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मैसर्स खर्वाईपुर सैण्ड माइनिंग (सविध/सरपंच, ग्राम पंचायत खर्वाईपुर), खसरा क्रमांक 570, ग्राम-खर्वाईपुर, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई भूमिों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में निम्न रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेली द्वारा किया जाएगा।
6. सस्टेनेबल सैण्ड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैण्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार चलान सुनिश्चित किया जाए।
7. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैण्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त शर्तों के पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राथिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सुचित किया जाए।

9. बैशर्स रामपुरम-1 सैण्ड खारी (सविध/सरपंच, ग्राम पंचायत सिमेंड), ग्राम-रामपुरम, तहसील-भोपालपट्टनम्, जिला-बीजापुर (सविधालय का नक्की क्रमांक 2422)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429160/2023, दिनांक 13/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। खदान ग्राम-रामपुरम, तहसील-भोपालपट्टनम्, जिला-बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 25, कुल क्षेत्रफल-1.215 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इटावली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता-12,150 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अधिन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती गोटा मीना, सरपंच, ग्राम पंचायत सिमेंड उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्की, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया

कि प्रस्तुत प्रस्ताव इन्द्रावती नदी से रेत उत्खनन का है, परंतु गूगल मैप में देखने पर विंतावागु नदी है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से समिति के समक्ष आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी अर्थांगित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई बाधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

**10. मेसर्स विष्णु प्रसाद ब्रिक अर्थ क्वारी (प्रो.-श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता), ग्राम-उपरकछार, ताहसील-फरसाबहार, जिला-जसपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2423)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 425464/ 2023, दिनांक 15/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (पीप खनिज) (बिना विनली चट्टा के) खदान है। खदान ग्राम-उपरकछार, ताहसील-फरसाबहार, जिला-जसपुर स्थित खसरा क्रमांक 253/4 एवं 252, कुल क्षेत्रफल-2.529 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-4,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. क्लटीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 26/08/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शक्ति रंजन साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उपरकछार का दिनांक 24/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान किंग प्रोसेसिंग क्वारी क्लोजर प्लान एन्ड इन्हायलमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के पु ज्ञापन क्रमांक 833-36/खनि./खज./2023 रायगढ़, दिनांक 27/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के ज्ञापन क्रमांक 737/खनि.शा./2023 जसपुर, दिनांक 24/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के आपन क्रमांक 736/खनि.शा./2023 जसपुर, दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार वक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर बांध, एनिकाट, मयन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मस्जिद, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. मू-स्थलिय - भूमि खसरा क्रमांक 252 श्री विष्णु प्रसाद साहू तथा श्री धनश्याम प्रसाद एवं खसरा क्रमांक 253/4 श्री अनुरा कुमार श्री ईग्नासियुस एवं श्री प्रदीप कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों की सहमति पत्र प्रस्तुत किया गए है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्री विष्णु प्रसाद साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जसपुर के आपन क्रमांक 584/खनि.शा./2023 जसपुर, दिनांक 30/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
9. पन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र - कार्यालय पनमण्डलाधिकारी, जसपुर पनमण्डल जिला-जसपुर के आपन क्रमांक/मा.वि/2020/3952 जसपुर, दिनांक 10/08/2020 से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घाम-उपरकाछार 1 कि.मी., स्कूल घाम-उपरकाछार 1 कि.मी. एवं अस्पताल लडबीघा 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है। तालाब 540 मीटर एवं प्रवालमंजी घामीय सड़क 130 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विंटिकली पील्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिपसोलॉजिकल रिजर्व 50,580 घनमीटर, गार्डनेबल रिजर्व 43,920 घनमीटर एवं रिजर्वेबल रिजर्व 42,802 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 832 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर विगनी बट्टा स्थापित नहीं किया जाएगा। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 80 प्रतिशत चलाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। खदान से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुसंधित क्यारी प्लान अनुसार कर्कर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	4,000
द्वितीय	4,000
तृतीय	4,000

वस्तु	4,000
धन	4,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेंट्रल प्रायमरी स्कूल अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कम से कम 3 पंक्तियों में कुल 400 नग वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (50 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीछी, फीसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समावहार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. गैर माइनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र में 30 वर्गमीटर क्षेत्र को वृक्ष एवं 28 वर्गमीटर क्षेत्र को ट्यूब वेल होने के कारण गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुसूचित क्वारी प्लान में किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के सम्मति विस्तार से बर्दा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.83	2%	0.2566	Following activities at Govt. Primary School, Lathbora	
			Plantation	0.531
			<b>Total</b>	<b>0.531</b>

17. सीईआर के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला लठबोरा में (नीम, पीपल, आम, कदम, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पीछी के लिए राशि 3,500 रुपये, फीसिंग के लिए राशि 25,000 रुपये, खाद के लिए राशि 500 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 8,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 37,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 25,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सीईआर के तहत वृक्षारोपण करने हेतु शासकीय प्राथमिक शाला लठबोरा के प्रधान पाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिष्कार करने (गर्न किया जाकर पक्के ईंटों का निर्माण) हेतु कहां-कहां, किन-किन मट्टों में उपयोग किया जाएगा तथा उन मट्टों को पर्यावरणीय स्वीकृति/सम्मति प्राप्त है अथवा नहीं? इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लीज क्षेत्र के भीतर लीज में भारी और 1 बीटर की बट्टी में कम से कम 3 बंजरियों में कुल 450 नग कृषारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में कृषारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीछी, बंजरिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समग्रवार प्राय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (गर्म किया जाकर पक्के ईंटों का निर्माण) हेतु कटा-कटा, किन-किन भट्टों में उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्टों को पर्यावरणीय स्वीकृति/सम्पत्ति क्या है अथवा नहीं? इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्दिष्ट किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
5. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढक कर रखे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्बन की जानकारी जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ सहित आर्कैडिक रिपोर्ट में समाहित करने हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम अधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फलाई एश को उचित रख-रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।
9. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन कृषारोपण किये जाने एवं रोपित पीछी का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री प्लानर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमांकन करकर खदान की सीमा क्षेत्र में विधमानुसार संचय स्थापित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।



13. प्रत्येक अर्द्ध पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लखित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लखित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत आगामी वर्षवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

**एजेन्डा आइटम क्रमांक-3:** परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अद्यतन पर्याप्त दिवार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड (सेमरिया लाईम स्टोन माईन), ग्राम-सेमरिया, तहसील-धमटा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नक्सी क्रमांक 1491)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 99127 / 2020, दिनांक 15/12/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने से जापन दिनांक 29/12/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित दूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सेमरिया, तहसील-धमटा, जिला-दुर्ग स्थित खदान क्रमांक 147, कुल क्षेत्रफल-3.096 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उपखनन क्षमता-25,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नक्सी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा खसामा सबसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उपरत खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिधारी के बीच दूरी उस सद्दा खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस विनरल क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को



(कलस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुभारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
3. मू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज की प्रती प्रस्तुत की जाए।
4. सीमा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रती प्रस्तुत किया जाए।
5. विगत वर्षों में किए गए खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ड्राफ्ट दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि व्यक्तिगत जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 06/05/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिगत जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ड्राफ्ट दिनांक 10/06/2021 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज एवं अनुरोध पत्र दिनांक 13/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।



नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परिषोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश अरोरा, सीनियर जरनल मैनेजर एवं श्री, सतीश मिश्रा, जरनल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार मैसर्स एनार्जीन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से शीकांत की, व्यवस्थापक, उचित पर्यावरण वैज्ञानिक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

1. पूर्ण में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सन्तुष्टात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सन्तुष्टात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई ही, पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरक्षित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोघ्राफ सहित प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोघ्राफ सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/2024/खनि.ति.2/खनिज/2020 दुर्ग, दिनांक 02/09/2020 द्वारा विगत वर्ष में क्रिये गये उखनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	खदान (टन)
जनवरी 2014 से दिसम्बर 2015	निरंक
2016	3,128.4
2017	1,822.74
2018	499.56
जनवरी 2019 से जून 2020	निरंक

3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उखनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमरिया(मि.) का दिनांक 28/05/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उखनन योजना — मॉडिफिकेशन इन एप्लाइड माईनिंग प्लान एलांग विथ प्रोपेसिब माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान निबंधक, भारतीय खान धुरी, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/दुर्ग/खन/खपो-1073/2017-रायपुर, दिनांक 24/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4203/खनि.ति./खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 519.8 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4203/खनि.ति./खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200

- मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह सार्वजनिक भूमि है। पूर्व में लीज की अवधि काफना के नाम पर थी। लीज डीड 20 वर्ष अक्टूबर दिनांक 18/09/2001 से 17/09/2021 तक थी। लीज का हस्तांतरण दिनांक 20/09/2013 को मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट के नाम पर किया गया। लीज डीड की कौता दृष्टि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
  7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
  8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/लक.अधि./2021/3999 दुर्ग, दिनांक 01/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 3.14 कि.मी. की दूरी पर है।
  9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी घाग-सेमरिया 0.9 कि.मी., स्कूल घाग-सेमरिया 1 कि.मी. एवं अस्पताल घाग 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.7 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 2 कि.मी. एवं ताड़ुला नला 3 कि.मी. दूर है।
  10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अमवालय, जैववैविध्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइन्टुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
  11. खनन खनदा एवं खनन का विवरण – जिपसोलॉजिकल रिजर्व 3,15,800 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,47,100 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,175 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट फुल्ली मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेस की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की स्थापित आयु 89 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊपरी स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। डिज़िग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। आगामी वर्ष की वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण प्रस्तुत एड्जुस्टेड माईनिंग प्लान नहीं है। अतः उक्त का सत्यापन कर संतोषित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति शिवनाथ नदी एवं पेयजल की आपूर्ति बोर्ड से की जाती है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना बताया गया है। जिसकी प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
  13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के खारी और 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग उल्लंघित होना बताया गया है।
15. प्रस्तुत गूगल मैप में बरखाती नाला खदान से लगा होना प्रतिपादित हुआ। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत गूगल मैप में त्रुटि है तथा लीज क्षेत्र की सीमा से नाले की न्यूनतम दूरी 50 मीटर है। उक्त स्थितियों को स्पष्ट करने हेतु समिति द्वारा उपसमिति का गठन कर निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण कर पुष्टि किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्तमव्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्रवाई की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. लीज बीड की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
3. धू-जल की उपखेपिता हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी एवं जल संसाधन विभाग से अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन होना पाया गया है। उपरोक्त उल्लंघन एवं लीज क्षेत्र की सीमा से नाले की न्यूनतम दूरी के संबंध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से निरीक्षण हेतु श्री किशन सिंह धुव एवं श्री एन.के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को सम्मिलित करते हुये दो सदस्यीय उपसमिति गठित की गई। उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करावेगी। अतः उपसमिति से जीव प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर अगिले कार्यवाही की जाएगी।
6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के इम्प्लेन दिनांक 14/02/2022 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अध्याप्त है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के इम्प्लेन दिनांक 14/02/2022 द्वारा श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं श्री एन.के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदनुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 21/02/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 16/03/2022 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"During the inspection Shri Deepak Tiwari, Mining Inspector Durg, Shri Shiv Patel Chemist, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhatla-Durg were also present, representatives from M/s J.K. Lakshmi Cement Limited, Dr. Sefish Mishra, General Manager, BL Bhati, Mine Manager, Shri Kumar Sachidanand and Mr. Dinesh Kumar were also present.

The document presented by the company were studied and found that lease grant in the area is for the duration of 30 years i.e. from 18/09/2001 to 17/09/2031.

- Leased area is marked with pillars and co-ordinates indicated over them (Photograph enclosed 1 to 12).
- The quantity of limestone quarried 41.05 metric tonne and royalty was paid for the same (Certificate enclosed Page 56).
- Mining is not carried out at present due to lack of environment clearance.
- All around plantation of lease area was observed and confirmed from the officers present (Photographs enclosed).
- Distance of one seasonal Water streams from lease area is 50m and more which was verified from the report of Mining Inspector, (Report enclosed page no.3)
- Report of Mining Inspector indicated that no excessive mining was performed above permissible limit (enclosed page no. 3).
- Consent to operate (CTO) with conditions from Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilai-Durg was issued to the company which is being followed by the company (Report enclosed page 76).
- As per the condition of CTO Air Quality Monitoring Report of proposed area which has been leased out is to be submitted in every six months.
- Required instruments for measuring air quality index under the process of installation. Controlled blasting, wet drilling shall be adopted for excavation.
- 7.5m wide area all around the lease area has left for plantation and about 1500 nos. of trees have been planted and process of further plantation was going on during the inspection and no excavation in 7.5m statutory boundary all along the lease area (Report enclosed page no. 67 and photographs).
- NOC from Central Ground Water Authority, CG Water Resources Department has been obtained (Certificate enclosed for ready reference page no. 71 and 67).
- CTO compliance and Air Monitoring Report has been also enclosed (Page no. 68 and 73).
- As per the reports of Mining Department and CG Conservation Board, no objectionable clause was found during prima facie inspection (Report Enclosed).

All the above mentioned discussion has been verified by the committee. The report is submitted for further action."

(3) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नसीब, निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपसमिति द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने तक आगामी कार्यवाही की जाएगी।

सद्वानुसार ई.आई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 के परिपेक्ष्य में उपसमिति द्वारा दिनांक 29/08/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ई) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/08/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

ई.आई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/02/2022 एवं 14/09/2022 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में दिनांक 07/11/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार—

1. आवेदित खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. लीज डीड की किराया वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार लीज डीड 10 वर्षों अवधि दिनांक 18/09/2021 से 17/09/2031 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।
3. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति शिवनाथ नदी से किये जाने बावजूत जल संसाधन विभाग का अनुमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भू-जल का उपयोग नहीं किया जाएगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में <https://uploadnow.in/fmZOR1Mk> द्वारा देखे जाने का उल्लेख है। समिति का मत है कि संशोधित माईनिंग प्लान की प्रति ई.आई.ए., रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. उपसमिति द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है—

"The above inspection report submitted to this office on 16/03/2022, the report includes all the aspects of providing TOR to the project proponent. The sub-committee has thoroughly undergone through all the documents, records and also visited the site under consideration. Therefore it is recommended to issue TOR to the project proponent, mentioning the additional condition to fulfill thereafter if found necessary in any later stage."

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कल्याण कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4203/खनि. ति./खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानों क्षेत्रफल 519.8 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-सेमरिया) का रकबा 3.098 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-सेमरिया) को मिलाकर कुल रकबा 522.898 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलेक्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' कोटेवरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ़ लिक्विड (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्फार्मेट वलीयरिस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीकोआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iv. Project proponent shall submit the copy of Approved Mining Plan & incorporate in the EIA report.
- v. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.
- vi. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals preferably for creation of ECO park with details of works alongwith their estimates including land



cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सुचित किया जाए।

2. मेसर्स बोकी आर्किटेक्चर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री अभय कुमार सोनी), ग्राम-बोकी, तहसील-जशपुर नगर, जिला-जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1737)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/सीजी/एनआईएन/218363/2021, दिनांक 18/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमीषी होने से ज्ञापन दिनांक 24/07/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह क्षमाता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित सार्वजनिक पत्थर (गोथ खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बोकी, तहसील-जशपुर नगर, जिला-जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 292, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर है। खदान की उत्खनन क्षमता - 2,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 6,318 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 04/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति की समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 18/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति की समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।



**(ग) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/07/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आगोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्सवस्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एलईएसी, खलीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 13/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(घ) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक अली, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा गयी, प्रस्तुत जानकारी का अन्वेषण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

**1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—**

- a. पूर्व में साधारण पत्थर खदान क्रमांक 202, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, क्षमता- 2,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्राधिकरण, जिला-जहापुर द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई।
- b. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोसहस सहित प्रस्तुत की गई है। चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन ज्ञापन कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- c. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग कुआरक्षण किया गया है।
- d. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारख), जिला-जहापुर के ज्ञापन क्रमांक/309/खनि. शा./2021 जहापुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी ज्ञापन पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन
2012	निरंक	2017	157
2013	370	2018	100
2014	50	2019	824
2015	निरंक	2020	1,700
2016	निरंक	2021	300

समिति का मत है कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में दिये गये उत्पादन आंकड़ों की मात्रा में इकाई (Unit) का उल्लेख नहीं है। अतः विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में किये गये उत्पादन आंकड़ों की मात्रा में इकाई (Unit) का उल्लेख करनी है।

811

खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बोकी का दिनांक 25/09/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - रिवाइज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.) जिला-जसपुर द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित रिवाइज्ड क्वारी प्लान में जाबक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। अतः अनुमोदित रिवाइज्ड क्वारी प्लान के क्वेरियर लेटर (जाबक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के ड्रापन क्रमांक 157/खनि.शा./2021 जसपुर, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के ड्रापन क्रमांक 158/खनि.शा./2021 जसपुर, दिनांक 28/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे स्कूल, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. लीज का विवरण - पूर्व में लीज श्री विरेन्द्र के नाम पर थी। लीज डीक 30 वर्षों अवधि दिनांक 11/05/2012 से 10/05/2042 तक की अवधि हेतु है। उक्त लीज का हस्तांतरण दिनांक 19/11/2018 को श्री अमर कुमार सोनी के नाम पर किया गया है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय वनमंडलाधिकारी, जसपुर वनमंडल, जसपुर के ड्रापन क्रमांक/मा.वि./2013/800 जसपुर, दिनांक 06/03/2012 के प्रमाण पत्र में आवेदित क्षेत्र हेतु अनापत्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। अतः लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-बोकी 530 मीटर, स्कूल ग्राम-बोकी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल जसपुरनगर 12.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.7 कि.मी. दूर है। नदी 1.2 कि.मी. एवं तालाब 385 मीटर की दूरी पर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्डुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।

12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिब्रोनीजिकल रिजर्व 3,51,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,30,767 टन एवं रिक्वर्डेबल रिजर्व 1,34,890 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,801 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 22 वर्ष है। लीज क्षेत्र में इन्फार स्थापित नहीं है एवं इन्फार स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टाफिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,318
द्वितीय	6,318
तृतीय	6,318
चतुर्थ	6,318
पंचम	6,318

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, जल आपूर्ति स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 415 नव वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा डाम पंचायत बोर्ड की अंतर्गत बोकी पहुँच मार्ग की दोनों तरफ 200 नव वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त भणना किया जाना आवश्यक है। साथ ही पहुँच मार्ग की लम्बाई (नक्शे में अर्थात् दस्तावेज सहित दस्तावेज तुर एवं खसरावार सहित) के अनुसार उपयुक्त वृक्षों का चयन कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी से किये गये उत्खनन आकड़ों की मात्रा में इकाई (Unit) का उल्लेख करते हुए खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. अनुमोदित सिव्वाइज क्वारी प्लान के कन्ड्रिंग लेटर (जाबक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अखतान अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, जल आपूर्ति स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
7. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विकस न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःस्थाप हेतु किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / ध्यान के दौरान निरीक्षण कतए जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना कर कॉन्फिरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) हेतु पर्युष मार्ग की लम्बाई (नक्शे में अक्षरों देखांतर सहित दर्राती हुए एवं सक्षार सहित) के अनुसार उपयुक्त कृष्टों का खपन कर सीईआर (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खपन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. प्रतीक्षित आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आलय का खपन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लक्षित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आलय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लक्षित नहीं है।

तदनुसार एसईए.सी., प्रतीक्षित के ज्ञापन दिनांक 09/11/2022 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/08/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

**(इ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/08/2023:**

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/12/2022, दिनांक 14/03/2023, दिनांक 29/05/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन

प्राप्त करने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन किया जाना बताया गया है, जो अद्यतन है। एस.ई.ए.सी. के ड्राफ्ट दिनांक 09/11/2022 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिकेवल प्रेषित करने हेतु अनुरोध पत्र लेख किया था, जो अद्यतन है।

उपरोक्त के परिषेध में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिकेवल हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाना आवश्यक है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ड्राफ्ट क्रमांक/310/खनि. शा./2021 जशपुर दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी प्रस्ताव पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2001	90	2012	165
2002	235	2013	240
2003	120	2014	60
2004	88	2015	580.1
2005	निरक	2016	28.1
2006	55	2017	10
2007	10	2018	77
2008	795	2019	185.8
2009	600	2020	480
2010	360	2021	312
2011	180		

प्रस्तुतीकरण के दौरान परिकेवल प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ड्राफ्ट क्रमांक/309/खनि. शा./2021 जशपुर दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी प्रस्ताव पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी अनुसार

2017	157
2018	100
2019	824
2020	1,700
2021	300

समिति का मत है कि प्रस्तुत रिवाइज्ड क्षारी प्लान अनुसार प्रस्तावित ग्रीन खनिज की स्पेसिफिक डेविटी 2.6 (1000 kg/m<sup>3</sup>) है। प्रस्तुत विधे गये दोनों जानकारी अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में भिन्नता है, अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर इस संका में स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. रिवाइज्ड क्षारी प्लान उप-संचालक (ख.प्र.), जिला-सुरगुजा के ड्राफ्ट क्रमांक 287/खनिज/खनि.3/उत्खनन यो./2022-23 दिनांक 16/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. भूमि संबंधी दस्तावेज (पी-2, खसरा नक्शा) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र सांख्यिक भूमि है।
5. कार्योन्मुख वनसंरक्षणविभाग जयपुर वनसंरक्षण, जिला-जयपुर को ज्ञापन क्रमांक/बा.वि./2012/800 जयपुर, दिनांक 08/03/2012 से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी की मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में रखा जाना बताया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संकलित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विख्या न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःसंग्रह हेतु किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / प्रमाण के दौरान निरीक्षण कराए जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ऊपरी मिट्टी की मात्रा के अनुसार ही ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 415 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 8,300 रुपये, बंसिंग के लिए राशि 55,000 रुपये, खाद के लिए राशि 5,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 80,300 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 48,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना कर कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) के तहत 200 मीटर लम्बाई के पट्टीय मार्ग के दोनों तरफ (नक्शे में अंशित दशांतर सहित दर्शाते हुए एवं खसरा क्रमांक 17/1) वृक्षारोपण हेतु विमानानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.8	Following activities at nearby, Village-Boki	
			Plantation	2.855
			<b>Total</b>	<b>2.855</b>

सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण के तहत (नीम, आम, अमरुद, अर्जुन एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नम पौधों के लिए राशि 4,000 रुपये, बंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 93,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,92,000 रुपये हेतु

घटकवार खय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बोकी के सहमति उपरोक्त सहायोग्य स्थान के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

10. माइनिंग लीज होव के अंदर सभ्य वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का स्वरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सभ्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. प्रत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सभ्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सभ्य पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लखित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित सभ्य पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियम का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रलंबन का प्रकरण लखित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्बन्धि से निम्नानुसार निर्णय लिखा गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का कालन प्रतिवेदन हेतु प्रत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के डायन क्रमांक/309/खनि. शा./2021 जसपुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के डायन क्रमांक/310/खनि. शा./2021 जसपुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की प्रमाणित जानकारी में भिन्नाता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर को पत्र लेख किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी की मात्रा के अनुसार ही ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त यथित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुचित किया जाए। साथ ही प्रत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर को पत्र लेख किया जाए।

3. मेसर्स बोकी (बीरोपानी) आर्किटेक्चर स्टोन क्वारी (प्री.- श्री अनमय कुमार सोनी), ग्राम-बोकी, तहसील-जसपुर नगर, जिला-जसपुर (सचिवालय का नक्शे क्रमांक 1750)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/22218/2021, दिनांक 28/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई होने से

ज्ञापन दिनांक 04/08/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह समस्त जिल्ला का प्रकरण है। यह पूर्व से संघालित सञ्चारण पथवर (गौण खनिज) खदान है। खदान घाम-बोधी, लहरील-जशपुर नगर, जिल्ला-जशपुर स्थित खाना क्रमांक 42/1, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर है। खदान की उत्पादन क्षमता - 3,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 44,313.68 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-बिल दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकी का विवरण -**

**(अ) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 04/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में वांछी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 18/08/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/08/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में वांछी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 28/07/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/07/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में वांछी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।



तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 13/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनागर अली, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा कक्षा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में सद्यःकाल पर्यटन खदान खनल क्रमांक 42/1, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टरपर, क्षमता-3,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सहायक पर्यावरण समाधान निर्धारण अधिकरण, जिला-जसपुर द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी कोटीप्राप्त सहित प्रस्तुत की गई है। चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- निर्धारित शर्तानुसार 200 नग कुसरोपन किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के ज्ञान दिनांक /310/खनि.सा./2021 जसपुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी ज्ञान पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2001	90	2008	795	2015	555.1
2002	235	2009	600	2016	26.1
2003	120	2010	360	2017	10
2004	65	2011	180	2018	77
2005	निरंक	2012	165	2019	185.8
2006	55	2013	240	2020	480
2007	10	2014	60	2021	312

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बोधी का दिनांक 16/09/2000 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - रिटर्न/खनल क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प.), जिला-सरगुजा के ज्ञान दिनांक 282/खनिज/खलि 3/उत्खनन की./2020-21 दिनांक 15/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के ज्ञान दिनांक 159/खनि.सा./2021 जसपुर, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जरापुर के आपन क्रमांक 160/खनि.शा./2021 जरापुर, दिनांक 28/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान में 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल एवं रेल लाइन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। पूर्व में लीज श्री संजय कुमार गुप्ता के नाम पर थी। लीज की 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 13/03/2001 से 12/03/2031 तक की अवधि हेतु है। उक्त लीज का हस्तान्तरण दिनांक 14/08/2020 को श्री अमर सोनी के नाम पर किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन सफ़लताधिकारी, जरापुर वनमण्डल, सामान्य जरापुर नगर के आपन क्रमांक/मा.वि./557 जरापुर, दिनांक 08/02/2001 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-बोकी 210 मीटर, स्कूल ग्राम-बोकी 3 कि.मी. एवं अस्पताल जरापुर नगर 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 8 कि.मी. दूर है। तालाब 280 मीटर दूर है।
10. परिसिंथितीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइन्टुटेड एरिया, परिसिंथितीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिपसोलैजिकल रिजर्व 4,68,000 टन, गार्डनेबल रिजर्व 2,21,589 टन एवं रिक्वैरेबल रिजर्व 1,99,412 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,384 वर्गमीटर है। आपन कास्ट सेमी मेकैन्डर्डज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेस की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्वारर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 2,000 वर्गमीटर है। जैक हेमर ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्राफ किया जाता है। वर्षावा प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	44,313.88
द्वितीय	44,313.88
तृतीय	44,313.88
चतुर्थ	44,313.88
पंचम	44,313.88

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।



13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 7.5 मीटर की पट्टी में 712 गम वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुखा हेतु फीसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया जाना बताया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा धाम पंचायत विरोधनी बोर्डो के अंतर्गत विरोधनी पट्टीय मार्ग के दोनों तरफ 200 गम वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना किया जाना आवश्यक है। साथ ही पट्टीय मार्ग की लम्बाई (नक्शे में अज्ञात देशांतर सहित दर्शाते हुए एवं सस्तरावार सहित) के अनुसार उपयुक्त पृष्ठों का घयन कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबद्धता प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुलयोग न करने, विह्वल न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / घमन के दौरान निरीक्षण कराए जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुखा हेतु फीसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना कर कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) हेतु पट्टीय मार्ग की लम्बाई (नक्शे में अज्ञात देशांतर सहित दर्शाते हुए एवं सस्तरावार सहित) के अनुसार उपयुक्त पृष्ठों (जैसे- पीपल, बरगद, बेत, कयन आदि) का घयन कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर लयन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सस्वाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. उत्तरीराज्य आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. शमीपवती प्राकृतिक जल स्रोतों की सुरक्षा करने तथा कोई हानि नहीं पहुंचाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।



8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का बयान पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसम्पु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्राप्य दिनांक 09/11/2022 के परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/08/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

**(इ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:**

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/12/2022, दिनांक 14/03/2023, दिनांक 29/05/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलसम्पु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन किया जाना बताया गया है, जो अप्रामाण्य है। एस.ई.ए.सी. के प्राप्य दिनांक 09/11/2022 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसम्पु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु अनुरोध पत्र लेख किया था, जो अप्रामाण्य है।

उपरोक्त के परिशिष्ट में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी की बाज का उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में रखा जाना बताया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विकस्य न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उसके निरीक्षण / प्रमग के दौरान निरीक्षण कराए जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ऊपरी मिट्टी की बाज के अनुसार ही ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 712 नग कुआरौपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधा के लिए राशि 14,240 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रुपये, खाद के लिए राशि 7,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,13,240 रुपये प्रधान वर्क हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 48,000 रुपये अगामी चार वर्क हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना कर कोर्पोरेट पर्यावरणीय इंडिकेस (C.E.R.) के तहत 200 मीटर लम्बाई के पट्टीय मार्ग के दोनों तरफ (नयी में



अर्थात् देशांतर सहित दशांश दूर एवं खसरा क्रमांक 30) कृषारोपण हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.6	Following activities at nearby Village-Biropani Boki	
			Plantation	2.855
			<b>Total</b>	<b>2.855</b>

- शीई.आर. के अंतर्गत कृषारोपण के तहत (मैच, आम, जमरुद, अर्जुन एवं जामुन) कृषारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नव पौधों के लिए राशि 4,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 93,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,92,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बिरौपानी बोकी के सहमति उपरोक्त अध्यायोग्य स्थान के संकक्ष में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- गाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सधन कृषारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सन्वाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- घनटीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- समीपवासी प्राकृतिक जल स्रोतों की सुरक्षा करने तथा कोई हानि नहीं पहुंचाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वधन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधिकार का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंदन हेतु घनटीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
- ऊपरी मिट्टी की मात्रा के अनुसार ही ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बाधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स श्री लक्ष्मीनारायण रिफाइन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, घान-बोरझरा, पोस्ट-तेन्दुआ, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 2238)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 411374/2022, दिनांक 20/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा घान-बोरझरा, पोस्ट-तेन्दुआ, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 191, 192/1, 192/2, कुल क्षेत्रफल-1,88,823 वर्गफीट (1,753 हेक्टेयर), क्षमता विस्तार के तहत सी-रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस. बार्स एण्ड रीड्स, एंगल, प्लेट/स्क्वायर, वैनल्स सेक्शन) क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 58,800 टन प्रतिवर्ष करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रूप 18.2 करोड़ होगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दयालाल पटेल, डीपैक्टोर एवं पर्यावरण सलाहकार के साथ मेसर्स श्री एण्ड एम सील्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जल एवं वायु सम्मति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस.बार्स एण्ड रीड्स, एंगल, प्लेट/स्क्वायर, वैनल्स सेक्शन आदि) क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28/03/2019 को जारी की गई है। जो कि दिनांक 30/01/2024 तक वैध है।
- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापी संबंधी जानकारी -

- निकटतम आवादी घान-अडोली 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। चंडा हाई स्कूल 2.2 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन उरकुटा 8.84 कि.मी. एवं जालन्धरी माल्टीस्पेशलिटी अस्पताल 4.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद

विमानपत्तन, माना, रायपुर 19.50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारन नदी 2.6 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 54 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबोधित किया है।
- 3. भू-स्वामित्व - भू-स्वामित्व/भूमि आबंधन संबंधी प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि मालिक श्री लक्ष्मीनारायण शिवल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है।
- 4. जैविक सुरिया स्टेटमेंट - प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त -

S.No.	Land use	Area (in SQFT)
1.	Rooftop/ Builtup Area	64,249
2.	Area Under the Road and Paved Area	25,000
3.	Green Belt Area (33.88%)	63,920
4.	Open Area	35,454
<b>Total</b>		<b>1,88,623</b>

समिति का मत है कि ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत किया जाकर तदनुसार जैविक सुरिया स्टेटमेंट संशोधित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- 5. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था -

Name of Waste	Existing Capacity (TPA)	Proposed Capacity (TPA)	After Proposed Expansion (TPA)
End Cutting (M S Scrap) and Mis Roll	900	864	1,764
Mill Scale	150	144	-294
<b>Total</b>	<b>1,050</b>	<b>1,008</b>	<b>2,058</b>

- कार्यक्रम में उत्पन्न मिल स्केल को कंटेनर एलिय प्लांट को विकस्य किया जाएगा। मिस रोल एवं मिस कास्ट को इम्पेक्शन फर्नेस में पुनः उपयोग किया जाएगा। यूज्ड ऑयल/वेस्ट ऑयल को अधिकृत रिफाईनर का उपलब्ध कराया जाएगा। स्लेज को मेटल रिकवरी यूनिट को उपलब्ध कराया जाएगा। इम्पेक्शन फर्नेस की रिफाईनिंग से उत्पन्न रिफाईनरी वेस्ट को रिफाईनरी इकाइयों को रिफाईनिंग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। प्लांट से निकलने वाले ई-कचरा, लीड एचिड बैटरी को अधिकृत रिफाईनर का उपलब्ध कराया जाएगा।
- 6. रेन वॉटर हार्डनिंग व्यवस्था - रेन वॉटर हार्डनिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
- 7. विद्युत आपूर्ति स्रोत - परियोजना हेतु वर्तमान में 1.3 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। भ्रमरा विस्तार उपरोक्त परियोजना हेतु कुल 4.8 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा।

8. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी - वर्तमान में इरिगट पट्टिका के विकास हेतु क्षेत्रफल 63.820 हेक्टेयर (33.88 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के चारों तरफ कम से कम 20 मीटर की चौड़ी बट्टी में वृक्षारोपण आगामी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाए तथा वृक्षारोपण को ले-आउट प्लान के एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण का विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत करते हुये ले-आउट प्लान (केएमएल) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं प्रस्तुत ग्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट में निम्नानुसार तथा पाया गया :-

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में ग्री-टैल्ड प्रोडक्ट्स सामान्य-30,000 टन प्रतिवर्ष से 58,800 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है, जबकि प्रस्तुत ग्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट एवं प्रस्तुतीकरण में इण्डकेशन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग स्थापित होना बताया गया है।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ग्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 8 में कोल गैसीफायर आधारित रि-हीटिंग फर्नेस 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से 58,800 टन प्रतिवर्ष किया जाना उल्लेखित है, जबकि ग्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 11 में वर्तमान में इण्डकेशन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग स्थापित होना एवं 6 मीट्रिक टन गुणा 2 नग प्रस्तावित किया जाना तथा रि-हीटिंग फर्नेस को बदलकर हाट धारिजिंग आधारित रोलिंग मिल किया जाना प्रस्तावित है।
- iii. क्षेत्रीय कार्यालय, असीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि-टैल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस.आर एण्ड रीड्स, एंगल, प्लेट/स्वायर, चैनल्स, सेवशन आदि) संख्या - 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28/03/2019 को जारी की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इण्डकेशन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग भी स्थापित होना बताया गया है। अतः इण्डकेशन फर्नेस हेतु जल एवं वायु सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्री-मटेरियल के रूप में एम.एस. इंगोट/किलेट्स एवं कोल की जानकारी दी गई है। स्थापित इण्डकेशन फर्नेस में कच्चे माल हेतु कोई जानकारी नहीं दी गई है।

उपरोक्त के संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मांगा जाना आवश्यक है।

10. वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्था की जानकारी तथा प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी मांगा जाना आवश्यक है।

11. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त प्रदूषण भार की गणना की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।





12. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त जल प्रबंधन व्यवस्था (जल की मात्रा, स्त्रोत, उत्पन्न दूषित जल की मात्रा) की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. ऑनलाईन आवेदन में सी-सेल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता—30,000 टन प्रतिवर्ष से 58,800 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है, जबकि प्रस्तुत प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट एवं प्रस्तुतीकरण में इम्प्लान्ट फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुण्डा 2 नम स्थापित होना बताया गया है। इस संबंध में समीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत किया जाकर तदनुसार लेन्ड एरिया स्टेटमेंट संशोधित कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत करते हुये ले-आउट प्लान (केम्प्लेन) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 8 में कोल गैसीफायर आधारित रि-हीटिंग फर्नेस 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से 58,800 टन प्रतिवर्ष किया जाना उल्लेखित है, जबकि प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 11 में वर्तमान में इम्प्लान्ट फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुण्डा 2 नम स्थापित होना एवं 8 मीट्रिक टन गुण्डा 2 नम प्रस्तावित किया जाना तथा रि-हीटिंग फर्नेस को बदलकर हीट एजिनिंग आधारित सेलिंग मिल किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में समीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि-सेल्ड प्रोडक्ट्स (एन.एस.आर एम्ड सीड्स, एंगर, प्लेट/स्वकथर, फैनल, रोयशन आदि) क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्बन्धी नवीनीकरण दिनांक 28/03/2019 को जारी की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इम्प्लान्ट फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुण्डा 2 नम भी स्थापित होना बताया गया है। अतः इम्प्लान्ट फर्नेस हेतु पैठ जल एवं वायु सम्बन्धी की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. स्थापित इम्प्लान्ट फर्नेस में कच्चे माल हेतु जानकारी मात्रा सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्था की जानकारी तथा प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त प्रदूषण भार की गणना की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त जल प्रबंधन व्यवस्था (जल की मात्रा, स्त्रोत, उत्पन्न दूषित जल की मात्रा) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/03/2023 की परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/06/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अडालोवन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—



1. सि-सील्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस. बार्स एण्ड रीड्स, एंगल, प्लेट्स/स्लीवर्स, वैनल्स सेवजन) क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 58,800 टन प्रतिवर्ष हेतु ऑनलाईन अप्रेंटिस किया गया है। इण्डक्शन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुना 2 नग स्थापित नहीं किया जाएगा।
2. लैण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQFT)	Area (%)
1.	Builtup Area	64,248	34.06
2.	Road Area	19,198	10.18
3.	Green Belt Area	91,180	48.34
4.	Open Area	13,997	7.42
<b>Total</b>		<b>1,88,623</b>	<b>100</b>

3. कोल बेसड मैसीफायर सि-हीटिंग फर्नेस के लहलू ही सि-सील्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस. बार्स एण्ड रीड्स, एंगल, प्लेट्स/स्लीवर्स, वैनल्स सेवजन) क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 58,800 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन किया जाएगा।
4. प्रस्तावित औद्योगिक इकाई में इण्डक्शन फर्नेस स्थापित नहीं है। पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीयसगड़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा सि-सील्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस. बार्स एण्ड रीड्स, एंगल, प्लेट/स्लीवर्स, वैनल्स, सेवजन आदि) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्बन्धी नदीनीकरण दिनांक 28/03/2019 को जारी की गई है।
5. प्रस्तावित औद्योगिक इकाई में इण्डक्शन फर्नेस स्थापित नहीं है।
6. वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च दक्षता का बेट स्कबर लगाया गया है तथा प्रस्तावित कार्यकलाप उपरान्त वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित है।
7. वर्तमान में पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन 60 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 8,702 कि.ग्र. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाने से इस्ट उत्सर्जन की मात्रा 8,733 कि.ग्र. प्रतिवर्ष होगी।
8. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि परियोजना से जनित दूषित जल को कुलिंग हेतु पुनः उपयोग किया जाता है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरान्त जल प्रबंधन व्यवस्था (जल की मात्रा, स्रोत, उत्पन्न दूषित जल की मात्रा) के संबंध में विस्तृत विवरण/जानकारी काईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 24/12/2013 के अनुसार "All other non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates" के परियोजनाओं को बी-2 श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है।
10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक वा.अ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार

"The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

11. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ई-मेल दिनांक 27/04/2023 के माध्यम से निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई है:-

"Both CM of 2013 and Notification dated 20.07.2022 is self explanatory in nature."

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24/12/2013 के अनुसार लोक सुनवाई से छूट एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिव्हायसिंग इन्वायर्समेंट क्लीयरेंस अप्पर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फ़ैरस एण्ड नॉन-फ़ैरस) हेतु निम्न अधिसूचना टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.
- ii. Project proponent shall submit the plant layout plan alongwith KML file.
- iii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
- iv. Project proponent shall submit details of pollution load calculation (existing & after expansion) of Air, Water, Solid waste etc.
- v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- vi. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.
- vii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.
- viii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.
- ix. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

- x. Project proponent shall submit the details of waste water generation and its disposal facility / mechanism. Project Proponent shall also submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.
- xi. Project proponent shall submit the details of solid waste generation from the unit.
- xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.
- xvi. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xviii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xix. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of 50% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for 50% green belt development, then the unit shall carry 48.34% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of 50%.
- xx. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xxi. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.
- xxii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एल.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ की तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स कोसंगा डिकस अर्ब क्लो क्लोटी (प्री- बीमती रीमा जायसकाल), ग्राम-कोसंगा, ताहरील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नक्शे क्रमांक 2301)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 416074/ 2023, दिनांक 08/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान (बिना विनयी मद्देत के) है। खदान ग्राम-कोसंगा, ताहरील-लखनपुर, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 449/2, 448/2, 452/1 एवं 452/3, कुल क्षेत्रफल-1.478 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,000 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., जालीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पंचकज कुमार जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत ज्ञानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोसंगा का दिनांक 23/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवम् क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के पृ ज्ञापन क्रमांक 1821/ए/ख.नि./ख.ज./2022 रायगढ़, दिनांक 27/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 29/खनिज/ख.नि.1/2023 अंबिकापुर, दिनांक 11/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 29/खनिज/ख.नि.1/2023 अंबिकापुर, दिनांक 11/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एकल खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकॉट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 449/2 एवं 448/2 आवेदक तथा खसरा क्रमांक 452/1 एवं 452/3 बीमती गायत्री अपकाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. एस.ओ.आई. का विवरण - एस.ओ.आई., बीमती रीमा जायसकाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक



385/समिज/ख.सि.1/म.क.31/2021 अंबिकापुर, दिनांक 18/03/2022 द्वारा जारी की गई, जो एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी। एल.ओ.आई. की विधायक वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अंबिकापुर के आवन प्रमांक/तक.अधि./2486 अंबिकापुर, दिनांक 20/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-कोसंगा 410 मीटर, स्कूल ग्राम-कोसंगा 780 मीटर एवं अस्पताल लखनपुर 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22 कि.मी. दूर है। चौदनी नदी 135 मीटर, मौसमी नाला 80 मीटर, तालाब 800 मीटर एवं नहर 4.65 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविकि्रता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविकि्रता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिक्रियित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – गियोलॉजिकल रिजर्व 29,580 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 27,710 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 28,324 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी (उत्खनन के लिए आवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 820 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 28 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,053
द्वितीय	1,053
तृतीय	1,053
चतुर्थ	1,053
पंचम	1,053

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षाच्छादन कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में जारी ओर 1 मीटर की घट्टी में 310 नम वृक्षाच्छादन किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछी के लिए राशि 3,100 रुपये, बंसिंग के लिए राशि 80,000 रुपये, खाद के लिए राशि 15,500 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 50,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,48,600 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु

कुल राशि 6,62,000 रुपये आगामी वार वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के लक्ष्य विस्तार से उच्च स्तरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.05	2%	0.361	Following activities at Government Middle School Village- Kosanga	
			Water Tank Installation for drinking water	
			Water tank (1,000 litre)	0.12
			Supply Pipe	
			Pipeline & Installation	
			Running water arrangement in toilet	
			Pipeline, tap, sanitary ware drain line	0.15
			Annual maintenance	
			Donation of Books related to Environment Conservation	
			Books	0.10
Steel Almira				
<b>Total</b>		<b>0.37</b>		

16. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान लीज क्षेत्र को के.एम.एल. से अवलोकन करने पर लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में लगभग 352 मीटर की दूरी पर विमनी स्थापित पाया गया है। अतः समिति का मत है कि उक्त दर्जित विमनी में खदान स्थापित है अथवा नहीं के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बस्नोला से जानकारी मांगा जा आवश्यक है।
18. परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तावित क्षेत्र में संबन्ध निट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने एवं विमनी स्थापित नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. प्रस्तुतीकरण के दौरान लीज क्षेत्र को के.एम.एल. से अवलोकन करने पर लीज क्षेत्र के निकट 10 मीटर से ऊंची सड़क है। इस संख्या में प्रस्तुतीकरण के दौरान

*Handwritten signature*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त सड़क, निजी भूमि में स्थित है। जो व्यवस्था को तहत अज्ञातगमन हेतु बनाया गया है एवं राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेज बी-1 में पटवारी द्वारा अनुमोदित खसरा क्रमांक 448/2 एवं 449/2 को निजी भूमि होने का उल्लेख है।

20. पर्याप्त डस्ट उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु निर्दिष्ट जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. माइनिंग लीज क्षेत्र को अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं संश्लिष्ट पौधों का सारवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वारण्य, वन और जलसंपु परिवारण मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804/अ, दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उत्सर्जन सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित क्षेत्र में केंद्रल मिट्टी उत्सर्जन का कार्य किये जाने एवं विमनी स्थापित नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र को कं.एन.एन. से अवलोकन करने पर लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में लगभग 382 मीटर की दूरी पर विमनी स्थापित पाया गया है। अतः उक्त दर्शित विमनी में खदान स्थापित अथवा नहीं के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-सरगुजा को पत्र लेख किया जाए।

एतानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 15/05/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक, भौतिकी तथा खनिकर्ण, नवा रायपुर के पृ. आपन क्रमांक 3831/खनि 02/उ.प.-अनुविष्ठा./ग.क्र. 50/2017(4) नवा रायपुर, दिनांक 05/06/2023 जिसके अनुसार "छत्तीसगढ़



गौण खनिज निधन, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 28/08/2020 (प्रकाशन दिनांक 30/08/2020) के नियम 42 के उप-नियम (5) परन्तु के तहत संघालक को प्रदत्त अधिकार प्रयोग करते हुये, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है। होना बताया गया है।

2. प्रस्तावित क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने एवं किन्हीं स्थापित नहीं किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सरगुजा के प्रापन क्रमांक 807/खनिज/खलि.1/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 13/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.987 हेक्टेयर है। साथ ही उक्त पत्र में यह भी उल्लेखित है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के प्रापन दिनांक 11/01/2023 द्वारा जारी किये गये पत्र में कृदिवस जयेश्वर राम आ. श्री मोहर साथ की खदान की जानकारी नहीं दी गई थी।

कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (गर्न किया जाकर पक्के ईंटों का निर्माण) हेतु कहा-कहां, किन-किन भट्टों में उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्टों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. सी.ई.आर. एवं क्लस्टरिंग कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छातीसमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं क्लस्टरिंग का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
5. मासलीय एन.डी.टी., प्रिजिन्ल बैंक, नई दिल्ली द्वारा क्लस्टर पारमेटेस विस्जुड भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्बन्धि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सरगुजा के प्रापन क्रमांक 807/खनिज/खलि.1/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 13/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.987 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-कोसंगा) का क्षेत्रफल 1.478 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-कोसंगा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.445 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तित करने (गर्भ कियत जाकर पक्के ईंटों का निर्माण) हेतु कहां-कहां, किन-किन मट्टों में उपयोग किया जाएगा तथा उन मट्टों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी एच. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सहायता अनुसंधान की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स कोसंगा डिवस सर्व वले क्वारी (प्रो.- श्रीमती रीमा जाक्सवाल) को ग्राम-कोसंगा, तहसील-लखनपुर, जिला-समनुज के खसरा क्रमांक 448/2, 448/2, 452/1 एवं 452/3 में स्थित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान (बिना विमर्श मट्टा के) कुल क्षेत्रफल-1.478 हेक्टेयर, क्षमता-1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्सिप्ट-05 में वर्णित शर्तों के अधीन सहायता पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

उक्त स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स सीदा आईनरी स्टोन मार्टिन (प्रो.- श्री राजेश कुमार जैन), ग्राम-सीदा, तहसील-खडगवा, जिला-मनेन्द्रगढ़-बिरभिरा-भरतपुर (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 2329)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 420770/ 2023, दिनांक 08/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित सधारण पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सीदा, तहसील-खडगवा, जिला-मनेन्द्रगढ़-बिरभिरा-भरतपुर स्थित खसरा क्रमांक-190, कुल क्षेत्रफल-2.1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-17,902.48 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/04/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा, प्रस्तुत जानकारी को अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में सधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 190, कुल क्षेत्रफल-2.1 हेक्टेयर, क्षमता-17,902.48 टन (8,393.73 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्रधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 27/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2026 तक वैध है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"3A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की कला जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2021 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन इतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में दिनांक 28/04/2023 को आवेदन किया गया है, जो आज दिनांक तक अद्यतन है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन इतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अदिकपुर में दिनांक 28/04/2023 को आवेदन किया जाना बताया गया है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्यापन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत करके हुये सख्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन इतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- iii. निर्धारित तर्कानुसार 480 नव वृक्षारोपण किया गया है।  
 iv. कार्यालय कलेक्टर खनिज सख्त, जिला-एम्.सी.डी. के डायन क्रमांक 171/खनिज/उ.प./2023 एम्.सी.डी. दिनांक 08/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016-17	निरंक
2017-18	निरंक

- v. कार्यालय कलेक्टर खनिज सख्त, जिला-एम्.सी.डी. के डायन क्रमांक 141/खनिज/उ.प./2023 एम्.सी.डी. दिनांक 18/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018-19	6.390
2019-20	5.895
2020-21	5.055
2021-22	6.095

*[Handwritten signature]*

समिति का मत है कि दिनांक 01/02/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अपेक्षा जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेन्डा का दिनांक 22/06/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लेयर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक 1973/खनिज/ख.लि.2/2018 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/01/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम.सी.बी. के द्वारा क्रमांक 142/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. दिनांक 15/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम.सी.बी. के द्वारा क्रमांक 142/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. दिनांक 15/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, नरघाट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज की विजय कुमार जैन के नाम पर थी। लीज डीड 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 06/12/2018 से 05/12/2048 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड का हस्तांतरण दिनांक 01/02/2023 को श्री राजेश कुमार जैन के नाम पर किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के द्वारा क्रमांक/मा.वि./2443 बैकुण्ठपुर, दिनांक 28/07/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-सेन्डा 350 मीटर, स्कूल ग्राम-सेन्डा 1 कि.मी. एवं अस्पताल विरमिरी 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 8.35 कि.मी., तालाब 1.17 कि.मी., मौसमी नाला 50 से 100 मीटर एवं नहर 9.85 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेकली कॉन्सुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

11. खनन संघटा एवं खनन का विवरण - अनुमोदित वार्षी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 2,94,000 टन (1,06,000 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 2,06,577 टन (73,420 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,74,740 टन (62,407 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,14,068 टन (76,452 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 1,25,845 टन (44,873 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,06,798 टन (38,142 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,451.28 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सीमी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 16,548.72 घनमीटर है, जिसका उपयोग रेन्ड्र हील-ट्रेड, ब्लास्टिंग हेतु स्ट्रेनिंग सामग्री के रूप में किया जाएगा। इसके उपरोक्त (यदि हो तो) शेष ओवर बर्डन की मात्रा को लीज क्षेत्र के समीप सहायता प्राप्त भूमि (खसत क्रमांक 94/3) पर भण्डारित किया जाएगा एवं उपरोक्त ओवरबर्डन को माईने क्षेत्र के पुनर्भरण में उपयोग किया जाएगा। बंध की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हेमर से ट्रिलिंग किया जाता है। ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। लीज क्षेत्र में ब्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण निर्वहन हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। पर्यावर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2023-24	17,902.46
2024-25	17,902.46
2025-26	17,902.46
कुल	53,707.38

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति सू-जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेंट्रल प्रायण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 882 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 450 नम वृक्षारोपण किया गया है एवं उक्त की अतिरिक्त 432 नम वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 4,320 रुपये, फंसिंग के लिए राशि 75,000 रुपये, खाद के लिए राशि 44,100 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 50,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रुपये, इन प्रकार प्रथम वर्ष हेतु कुल राशि 2,73,420 रुपये एवं आगामी चार वर्षों हेतु कुल राशि 7,76,400 रुपये का परतंत्रार व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment	Amount for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)
------------------------------	----------------------------------	---------------------------	---

*Handwritten signature/initials*

Rupees)	to be Spent	(in Lakh Rupees)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
9.03	2%	0.18	Following activities at Village-Saında	
			Plantation with fencing around Pond & 5 year AMC	0.34
			<b>Total</b>	<b>0.34</b>

सी.ई.आर. के अंतर्गत घास-सैदा के तालाब (खसरा क्रमांक 733 एवं 734) के घासों तथा जल एवं जानुन के विभिन्न प्रजातियों के रोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नव पौधों के लिए राशि 2,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 5,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 10,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 24,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिती का मत है कि तालाब के घासों तथा कृषासंरक्षण करने हेतु राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने सख ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराए जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. स्पूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. उत्तीर्ण आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सख कृषासंरक्षण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाघमंडी विल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लंबित नहीं है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, खाता में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तालाबय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 01/02/2023 से किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की अपलन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित बनाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. तालाब के घाटे तरफ वृक्षारोपण करने हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बंदिश जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/08/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/08/2023:

समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट आई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि उनके द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 26/04/2023 को आवेदन पत्र ड्रेफिल किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत करते हुये सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर्तु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाला, जिला-मनेन्द्रगढ़-धरमिरी-भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 111/खनिज/उ.प./2023 एन.सी.डी. दिनांक 07/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
फरवरी 2023	650
मार्च 2023	40
अप्रैल 2023	510
मई 2023	950

3. तालाब के घाटे तरफ वृक्षारोपण करने हेतु ग्राम पंचायत सौदा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।



4. सी.ई.आर. कार्ड एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्ड के नॉन्डिस्ट्रिब्यूटिव एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्ड पूर्ण किये जाने के उपरांत उचित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एम.जी.टी., प्रिंसिपल सेंच, नई दिल्ली द्वारा सतवीड पाप्येड क्लियरेंस भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पेशित आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय ब्लॉकटर (खनिज शाखा), जिला-एम.जी.टी. के ज्ञापन क्रमांक 142/खनिज/उ.प./2023 एम.जी.टी. दिनांक 15/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरक है। आवेदित खदान (ग्राम-सीदा) का रकबा 2.1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सख्त अनुशंसा की जाती है।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेरास सीदा आईनटी स्टोन माईन (प्रो.- श्री राजेश कुमार जैन) को ग्राम-सीदा, तटसील-खडगवा, जिला-मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर के खसरा क्रमांक 190 में स्थित संधारण पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.1 हेक्टेयर, क्षमता-17,902 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-08 में उचित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण ज्ञात आकलन प्राकिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

देखक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदिबुस शिर्की)

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति  
छत्तीसगढ़

(श्री बी.पी. मोन्टर्)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति  
छत्तीसगढ़



मैसर्स चुरईया सैण्ड माईनिंग (सचिव/सचयंघ, ग्राम पंचायत चुरईया)  
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 638, कुल क्षेत्रफल-1.173 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र  
2.212 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 0.9518 हेक्टेयर क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में  
ही रेत उत्खनन, प्लान-चुरईया, तहसील व जिला-कोरवा (छ.ग.) में चुरईया नाला से रेत  
उत्खनन क्षमता 5.710 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में ही जाने काली  
हती

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को  
बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्कादन की तारीख से पांच वर्ष तक की  
अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सैण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining  
Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स  
फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand  
Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement  
& Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन  
कराये किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गावड अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में  
आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गावड अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के  
पुनर्पूरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट,  
स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता  
पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (सीज  
घाटक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा,  
स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. सीज क्षेत्र के घाटी कोनी तथा सीमा लाईन के माध्य में सीमेंट के खर्च गणना  
आवश्यक है ताकि सीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर  
के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो  
पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 0.9518 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत  
क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा।  
रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक  
नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 5.710 घनमीटर प्रतिवर्ष से  
अधिक नहीं होगा।
9. नवनीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा  
माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने  
हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं बिंदु बिन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं बिंदु बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं डी-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। निचर बेड में नारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल विन्दित, सीमांकित एवं घेरेल क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोन्नों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेन्, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल लीज क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंधेरा उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाही की जायेगी।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों तथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले संचुजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की

जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिचालन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन सार्वजनिक अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इकट्ठे हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को शमल से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्रकृतिकला के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट, के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 400 नम पीधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पीधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीधों की सुखा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का सम्यक् पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीधों की सुखा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पीधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीधे के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफस सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में साथे जमा बने। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. वृक्षरोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पीधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षरोपण की पुष्टी हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) साथे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णगढ़ को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
10.97	2%	0.219	Following activities at Nearby Village- Chuiya	
			Plantation in Village Pond Boundary	0.354
			<b>TOTAL</b>	<b>0.354</b>

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिकेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत

किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। कृषारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जाएगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब की चारों ओर में कृषारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नम पीछी को रोपण किया जाएगा। कृषारोपण हेतु (आम, जाम, इमली आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछी के लिए राशि 2,500 रुपये, फंसिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद के लिए राशि 500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,000 रुपये, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल राशि 28,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,12,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.आर. एवं कृषारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोपरसाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कृषारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति ही सत्वापित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोम/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कतये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं जाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. उत्तीर्ण नवीन श्रमिक नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कोयला श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. श्रमिकों के लिए खाने स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकिसाक्षीय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद सामग्री के फैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।
34. श्रमिकों का समय-समय पर आयुपूर्वकाल हेल्थ सर्विलेंस कराया जावे।
35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्ण / भारत

सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारी के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संप्रेषण में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [parivesh.nct.in](http://parivesh.nct.in) पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा, एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथकण्डा एवं सीमांकन संघलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को



पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इसके पर विचार कर शर्तों की अनुपपूर्णा अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण न्यायिक पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उसके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्राक्कानी अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

  
सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

  
सचिव, एस.ई.ए.सी.

नेशनल अमलडीहा सैण्ड माईनिंग (प्रो- बी मिलेस चन्द भार्गव)

को फाट जीक खराब इलाक 512, कुल क्षेत्रफल-4.09 हेक्टर से कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल, प्वाण-अमलडीहा, लहमील-मस्तुरी, जिला-बिलसपुर (प्र.ग.) में सिवनाख नदी से रेत उत्खनन इलाका कुल 48,600 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। जत इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्काशन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सैण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Siltation Study) करायेंगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) काबल सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रती छः माह में प्रोपेस रिपोर्ट एन.ई.आई.ए.ए., कलकत्तागढ़ में प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आंश एवं वार्षिक सहित उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
7. लीज क्षेत्र के चारों ओर लकड़ सीमा लाईन के साथ में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
8. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
9. उत्खनन क्षेत्र 4.09 हेक्टर से कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। सैण्ड 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 48,600 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
10. नाननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्वाण एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

11. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित पिंड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसकी आंकड़े तालिका एन.ई.आई.ए. ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं पिंड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित पिंड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं पिंड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित पिंड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
12. रेत की खुदाई एवं भराई भूमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। क्वार क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
13. रेत का उत्खनन केवल पिन्हील, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई बैंक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
14. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षय न हो। किसी भी पुलिसिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई किरील प्रभाव न पड़े।
16. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उरी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कचुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संस्थापन आवश्यक है, आत इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
17. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। रात कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागी यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फर्क्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल फिन्काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण,



धन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होगी चाहिए।

19. रेत का परिवहन सार्वजनिक अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से हुके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को आमतौर से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
21. प्राकृतिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 800 नव पीढों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 बीट से 6 बीट ऊंचाई वाले पीढों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीढों की सुखा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का हल्क पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीढों की सुखा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परिशोधन प्रस्तावक का रहेगा।
22. रोपित किये जाने वाले पीढों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीढों के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी आर्वाधिक रिपोर्ट में साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
23. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करती हुये मूल पीढों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
24. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ आर्वाधिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
25. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31.42	2%	0.6284	Following activities at Nearby Village- Amaldiha	
			Plantation around the village pond	0.50
			<b>Total</b>	<b>0.50</b>

26. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 05 लाख में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. को उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आर्वाधिक रिपोर्ट में समाहित करती हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आचका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

27. सी.ई.आर. के अंतर्गत खाताब पर (आम, जामुन, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पौधों के लिए राशि 3,000 रुपये, ट्री-गार्ड के लिए राशि 4,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 88,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा राम पंचायत अमलझोहा के सहयोगी उपरंत पंचायत स्थान (खरवा क्रमांक 295) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
28. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरंत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
29. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आए, तब उन्हें खदान/उत्खनन/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागी, मण्डली एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. छत्तीसगढ़ नौव खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
33. कार्य स्थल पर यदि कोयिंग शक्ति कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे शक्तियों के आकाश की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
34. शक्तियों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकिणकारीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।
35. शक्तियों का समय-समय पर आयुष्यशैल हेल्थ सर्विलेंस कराया जावे।
36. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप शक्ति योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

37. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों को उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
38. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संतोषन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काश के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
39. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने से 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को शर्तों पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [parishesh.nic.in](http://parishesh.nic.in) पर भी किया जा सकता है।
40. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
42. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बन्दे की गयी नियमों, परिसंरक्षकमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संयोजन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
43. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विघटन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्मूलन एस.ई.आई.ए.ए.,

छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

44. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

  
सचिव सचिव, एस.ई.ए.सी.

  
सचिव, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स कुदुरमाल सैण्ड माईनिंग (ससपंच/सचिव, ग्राम पंचायत कुदुरमाल)  
की पार्ट ऑफ खाना क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल,  
ग्राम- कुदुरमाल, तहसील व जिला-कोरबा (छ.प्र.) में इसदेव नदी से रेत उत्खनन समेत  
कुल 38,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खाना पट्टे के निष्काशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सैण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनःपूरण (Replenishment) बाधित नहीं आसके, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसमूह, जीव एवं सूक्ष्म जीवी पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज क्षेत्र का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के नजद में सीमेंट की खम्भे बसाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. उत्खनन क्षेत्र 4 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 38,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के सारों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ों तालिका एस.ई.आई.ए. ए. प्रतीसंग्रह को प्रस्तुत किये जावें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज

क्षेत्र की अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन सीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर किया जाएगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरतल मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही बिंदु बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सीज क्षेत्र में निम्न रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रैलरों द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल बि-हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टांपडेन, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से छदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कचुओं के प्रजनन डुमईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंधेरा उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले एम्ब्रिजिटेड डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेहीय वायु की गुणवत्ता मासल सरकार, चर्मावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन सारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इकट्ठे हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को धक्का से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीछट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 600 नग पौधों का रोपण नदी छट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का सपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व प्रतिबोधना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्थात्वार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थात्वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35.50	2%	0.71	Following activities at Nearby Village- kudurmali	
			Plantation around the village pond	0.90
			<b>Total</b>	<b>0.90</b>

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 नग में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात्वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अथवा उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, जामुन, करंज आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पौधों के लिए राशि 3,000 रुपये, टी-गार्ड के लिए राशि 4,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के

64

लिए राशि 15,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 84,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कुदुस्मान के सहमति उपरोक्त पंचायतीय स्थान (खसरा क्रमांक 271) के संकेद में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं कृषासेवा कार्य के मासिक एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कृषासेवा का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आवेगी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागी, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतिपत्र प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ ग्रीन एगिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्राधान्यों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कौन्सिल भूमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भूमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. भूमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकिसिद्धीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अधवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।
34. भूमिकों का समय-समय पर आस्पेक्शनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जावे।
35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसूच्य वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अधवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी



निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्मरणा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निरस्त करने मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आरा-पारा व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सख्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [parivash.nic.in](http://parivash.nic.in) पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा, एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकी/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटनय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमाकार संयोजन) नियम, 2006 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विघटन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।



मैसर्स धरईपुर सैण्ड माईनिंग (सक्रिय/सुरक्षित, ग्राम पंचायत धरईपुर) को खसरा क्रमांक 570, कुल क्षेत्रफल-4.5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल, ग्राम ग्राम-धरईपुर, तहसील-कटघोरा, जिला-बरेilly (अ.प्र.) में अहिरन नदी से रेत उत्खनन क्षमता कुल 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्काशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सैण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग - गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Siltation Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) वास्तु सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के कभी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आसंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओरों तथा सीमा लाईन के साथ में बीमेंट के खम्भे बसाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. उत्खनन क्षेत्र 4.5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। क्षेत्र 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित किंड किन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े छात्रगत एस.ई.आई.ए. ए. छात्रावास के प्रस्तुत किये जायें; पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत



उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं बिंदु बिन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपरस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सातह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर किया जाएगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरतत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं बिंदु बिन्दुओं पर रेत सातह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सातह के पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर रेत सातह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। फेस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भरवाई भूमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल विन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सातह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सातह से 1 मीटर छोड़कर दोन्नों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टावपेज, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपरस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसकी आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, आत इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भरवाई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंधे उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागी तथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले क्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, संजालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपीलिन अथवा अन्य उपयुक्त वाहन से इको हुए वाहन से किया जाए ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उखानन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीलट से कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 600 नग पौधों का रोपण नदी तट पर, स्कूल में 200 नग तथा चहुंकरगं में 200 नग पौधे इस प्रकार कुल 1,000 नग पौधे रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का समझ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परिचयना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफस सहित जानकारी अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
22. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करती हुये नए पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पत्र कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35.92	2%	0.7184	Following activities at Village- Dhawaipur	
			Plantation	0.7184
			<b>Total</b>	<b>0.7184</b>

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपर्युक्त संबंधित घाम संघोषता से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
26. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (पीपल, जामुन, नीम, करंज, अंबला आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए लक्षि 5,000 रुपये, ट्री-टार्क एवं

कंसिग के लिए राशि 24,340 रुपये, खाद के लिए राशि 7,500 रुपये, सिंचाई तथा रक-रखाव आदि के लिए राशि 30,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 71,840 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 30,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा राम पंचायत जवाईपुर के सहमति उपराल जलसंधारण स्थान (खसरा क्रमांक 507, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपराल गठित त्रि-पक्षीय समिति से सल्लाहित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवें, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराया आपकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्राधान्यों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों अनुसंधित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कंसिग भूमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भूमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिले परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. भूमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकिसमाकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में माल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जाये।
34. भूमिकों का समय-समय पर आर्यदूरेक्षणल हेल्थ सर्वेलेस कराया जाये।
35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी



निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्वरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से चलाने न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के जल-वायु व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सख्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [pariwesh.nic.in](http://pariwesh.nic.in) पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के चलाने हेतु की गई कार्रवाहों की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के चलाने की मॉनिटरिंग की जाएगी।
40. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाई जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से चलाने करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटग्रहण अधिष्ठित (प्रबंधन हथकण्डा एवं सीमांकन संयोजन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की सम्पुर्णता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने कायदा निर्णय ले सके। छदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उनके संबंधित कार्यालय, जिला-स्तर एवं तहसील केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

  
सदस्य सचिव, एन.ई.ए.सी.

  
सदस्य, एन.ई.ए.सी.



नेहरू कोसंग बिल्ड अर्ब कले क्वार्टी (प्रो- बीमती रोमा जायसवाल) को खसरा क्रमांक 449/2, 448/2, 452/1 एवं 452/3, घाम-कोसंग, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा, कुल लीज क्षेत्र 1.478 हेक्टर, मिट्टी उत्खनन (बीम खनिज) (बिना बिमनी भट्टा के) समता - 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किन्ही क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति लागू नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.478 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (बीम खनिज) (बिना बिमनी भट्टा के) समता - 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर चकर्त मुन्डरे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेंगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किन्ही सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड-लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुल्य प्रभाव में ली जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सलाही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा पुनरापयोग हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोल्डिटी की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सलाही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
8. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न फ्ल्यूजेंटिव अस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रोड, सड़क क्षेत्र

भराई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन / संचारण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनियमित मानकों (जी पी कटोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
10. ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को भू-भरण एवं रोड के संचारण हेतु उपयोग किया जाए।
11. फलाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जाये। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये की फलाई ऐश उड़कर आस-पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
12. उत्खनन के दौरान इटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्करेटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का तूट उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊंचाई 03 मीटर तथा स्लॉप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीकों से वृक्षारोपण किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु नाईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईट भट्टा क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / गार्लेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
15. मिट्टी, फलाई ऐश एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.05	2%	0.361	Following activities at.	

*Handwritten signature/initials*

			Government Middle School Village- Kosanga
			Water Tank Installation for drinking water
		Water tank (1,000 litre)	0.12
		Supply Pipe	
		Pipeline & Installation	
			Running water arrangement in toilet
		Pipeline, sanitary drain line	0.15
		tap, ware	
		Annual maintenance	
			Donation of Books related to Environment Conservation
		Books	0.10
		Steel Almira	
		<b>Total</b>	<b>0.37</b>

17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
18. सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं सर्वेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
19. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/खण्ड/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लेखित क्षेत्र (घाटी तरफ 01 मीटर गौडी बेल्ट), हील रोड, ओवरकॉर्डेन जम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 310 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
21. प्रारम्भिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 310 मग पीछे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशु, आम, इमली, अर्जुन, शीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (क्या कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए।

स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ड्रॉग पंचायत द्वारा किन्हीं क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 6 फीट से 8 फीट ऊँचाई वाले पीठों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

22. लेपित किये जाने वाले पीठों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीठों के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्थात्वारिक रिपोर्ट के साथ जमा करे।
23. गाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सभ्य वृक्षारोपण किये जाने एवं लेपित पीठों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पीठों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
24. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थात्वारिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण ज्ञान आकलन प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिवर्षित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
26. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
27. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसमुदायों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
28. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय अध्ययन योजना के अनुसार किया जाए।
29. कार्य स्थल पर यदि कंमिग भूमि कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भूमिओं के आकलन उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
30. भूमिओं के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विविधस्तरीय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
31. भूमिओं का समय-समय पर आवश्यकतानुसार हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
32. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
33. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण कन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
34. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कपरेशा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में

किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरन्धन के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

35. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट [parivest.nic.in](http://parivest.nic.in) पर भी किया जा सकता है।
36. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
37. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये वसतावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
38. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
39. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटनमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमाकार संयोजन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
40. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विद्यमान अथवा परिवर्तन होने की वजह से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों को उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाधत निर्णय ले सके। सहान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

42 पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।



सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.



अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स सीदा अर्जिंनरी स्टोन माईन (प्री- श्री राजेश कुमार जीन)  
की खदान क्रमांक 190, कुल लीज क्षेत्र 2.1 हेक्टेयर, ग्राम-सीदा, तहसील-खड़गवा,  
जिला-बनेन्द्रगढ़-दिरमिरी-भरतपुर में साधारण पत्थर (पीप खनिज) उत्खनन - 17.902  
टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को  
बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.1 हेक्टेयर अथवा  
छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम  
हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन  
17.902 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन  
कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय  
स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो)  
के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की दिशा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन,  
मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों को  
सहज रहेगी।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा  
माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने हेतु  
परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधाभास निपुण करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी  
नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए,  
अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा कूलरिंग हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल  
के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोल्पीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को  
किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया  
जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की  
जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु  
परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण  
संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया  
जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after passing mining  
operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के  
कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रेसिंग  
(re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा,  
जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना  
प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक महीने के भीतर  
प्रस्तुत किया जाए।

8. न्यू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केंद्रीय न्यू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी विन्नी / वेट / घाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्वार, स्क्रीन, ट्रांसलर फाईट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का ड्रेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न पर्यावरणीय डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संवहन क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम सप्लेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचारण सुनिश्चित किया जाए। विन्क ड्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिकेहीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, जल और जल वायु परिवर्तन संचालन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के घाटी तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की छोड़ी चट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस चट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर फुलक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को फुलक से दूर से विन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विखरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के परछात बने चट्टों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा खनिज वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परिक्षेपण प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिस्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु गार्डन वीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेंनिंग वॉल / गारलैन्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कचई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment	Percentage of Capital	Amount for CER	Amount Proposed & Details for CER Activities
--------------------	-----------------------	----------------	--

*(Signature)*



(in Lakh Rupees)	Investment to be Spent	Activities (in Lakh Rupees)	(in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
9.03	2%	0.18	Following activities at Village-Sainda	
			Plantation with fencing around Pond & 5 year AMC	0.34
			<b>Total</b>	<b>0.34</b>

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करके हृदय प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आगका जाल-बद्धकृत होगा। वृक्षारोपण अस्तव्यस्त होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम-सैदा के तालाब के चारों तरफ आम एवं जामुन के विभिन्न प्रजातियों के रोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रुपये, कीलिंग के लिए राशि 2,000 रुपये, चांद के लिए राशि 1,000 रुपये, रक-रखाव आदि के लिए राशि 5,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 10,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 24,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सैदा के सटमति उपरोक्त पंचायतीय स्थान (खसरा क्रमांक 733 एवं 734) के संकेत में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ज्येष्ठ अधिकारी/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जल संसाधन पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/घट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आगके द्वारा कटये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
22. उपखनन हेतु निश्चित क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड ओवरबर्डन अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 450 वृक्षों का रोपण वृक्षारोपण किया जाए। हरित घट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्रकृतिकला के आकार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में तीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, कर्ज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सौरभ आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 420 नग पौधों का रोपण (कुल 870 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जब कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त

- प्लांटरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। प्लांटरोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफस सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
  25. माइनिंग क्षेत्र क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन प्लांटरोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्लांटरोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
  26. किये गये प्लांटरोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्थवर्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
  27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
  28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों में रेपुब्लिक डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
  29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत धातुमय मिनेरल्स द्वारा सीनाकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
  30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पीछर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों को संरक्षण एवं संरक्षण किया जाए।
  31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का सार उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। लूड ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
  32. पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं स्थान व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अपावित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
  33. उत्खनन क्रिया में भू-जल स्तर के उपर असंतुल्य प्रभाव में ली जाएगी एवं उत्खनन क्रिया में भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
  34. उत्खनन की क्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि लगीय स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में काम करने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
  35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
  36. कार्य स्थल पर यदि कौन्सिल श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों को आवास एवं सुख्य हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. शर्मिकाओं के लिए खानग स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकित्ताकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. शर्मिकाओं का समय-समय पर आरूप्येशनयल हेल्थ सर्विलेस कनान्ड आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, शर्मिका की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निर्यात के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [parivesh.nic.in](http://parivesh.nic.in) पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाहों की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण तैट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिभाषकटमय



और अन्य अधिष्ठित (प्रकाश एवं सीमापार संवहन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विघटन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तों निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करना।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिनों की समय अवधि में की जा सकती है।

  
सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

  
सदस्य, एस.ई.ए.सी.